राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार , 10 दिसंबर 2025
वर्ष 14, अंक 237, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

लेखपाल ने शिकायतकर्ता की मिलीभगत से किसान की गेहूं की फसल को जोतवाया..03

अभिभावकों ने परिषदीय विद्यालय देर से खुलने का लगाया आरोप..04

बैलट बूथ लूटने का हथकंडा था, सबको सलाह-कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए, ललन सिंह का संसद में हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- लोकसभा में चुनाव सुधारों और चुनाव प्रक्रिया पर हो रही चर्चा के दौरान जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ 'ललन सिंह' ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है. अपने भाषण के दौरान ललन सिंह ने न केवल ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का तार्किक जवाब दिया, बल्कि कांग्रेस के इतिहास, उनकी कार्यशैली और गठबंधन की राजनीति पर भी जमकर निशाना साधा. ललन सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुरानी 'बैलट पेपर' वाली व्यवस्था और कुछ नहीं, बल्कि 'बूथ लूटने का एक हथकंडा' थी, जिसे चुनाव आयोग ने खत्म कर देश की चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है।

'बैलट पेपर की वापसी मतलब बूथ लूट की वापसी'

सदन में अपने संबोधन के दौरान ललन सिंह ने विपक्ष की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें बार-बार बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की जा रही है. उन्होंने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि देश उस दौर को नहीं भूला है जब मतपेटियां लूटी जाती थीं. उन्होंने कहा, 'आप (विपक्ष) जिस बैलट पेपर की बात कर रहे हैं, वह दरअसल बूथ कैप्चरिंग का एक जरिया था. वह एक ऐसा हथकंडा था जिसके दम पर बाहुबल का प्रयोग कर चुनाव जीते जाते थे. चुनाव आयोग ने उस काले अध्याय को समाप्त कर दिया है और ईवीएम जैसी पारदर्शी तकनीक को अपनाया है।

ललन सिंह ने विपक्ष के दोहरे चरित्र को उजागर करते हुए कहा कि जब नतीजे उनके पक्ष में आते हैं, तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठते. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक इसी ईवीएम के दम पर सरकार चलाई. तब ईवीएम ठीक थी? जनता ने आपको 10 साल सत्ता में बैठाया तो मशीन ईमानदार थी, और आज जब जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही, तो मशीन में खराबी नजर आने लगी है?

उन्होंने हालिया विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा, 'जब आप हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जीत जाते हैं, तब ईवीएम बिल्कुल सही काम करती है. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतती हैं तो ईवीएम पवित्र हो जाती है. लेकिन जैसे ही हरियाणा, महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में भाजपा और एनडीए की जीत होती है, तो अचानक ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाने लगता है. यह दोहरा मापदंड अब देश की जनता समझ चुकी है।

'कांग्रेस के साथ जो गया, उसका विनाश तय'

राजनीतिक गठबंधन और क्षेत्रीय दलों की स्थिति पर बोलते हुए ललन सिंह ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी. उन्होंने अपने सहयोगी दलों और विपक्ष में बैठे क्षेत्रीय क्षत्रपों को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस का साथ देना मतलब अपनी राजनीति को खत्म करना है।

ललन सिंह ने सदन में गरजते हुए कहा,

'इतिहास गवाह है, कांग्रेस के साथ जो भी गया, वह खत्म हो गया. आप लोग (विपक्ष के साथी) भी सावधान हो जाइए. हमारी तो यही सलाह है कि जितनी जल्दी हो सके, कांग्रेस का साथ छोड़ दीजिए, वरना आपका हश्र भी बुरा होगा.' उन्होंने करुणानिधि और अन्य नेताओं का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने अपने ही सहयोगियों को जेल भेजने या राजनीतिक रूप से कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और राजद पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'बिहार में कुछ लोग नतीजे आने से पहले ही शपथग्रहण की तारीख बता रहे थे. वे खुद को मुख्यमंत्री मान बैठे थे. 20 जिलों की यात्रा की, बड़े-बड़े दावे किए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? जहां-जहां गए, वहां-वहां सूपड़ा साफ हो गया. जनता ने उनके अहंकार को उसी ईवीएम के जरिए जवाब दिया है, जिसे वे आज कोस रहे हैं।

संवैधानिक संस्थाओं पर प्रभावः 'आइना आप देखिए'

विपक्ष द्वारा मोदी सरकार पर चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने के आरोपों पर ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को उनका ही अतीत याद दिलाया. उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्था के काम में दखल नहीं देती और न ही उन्हें प्रभावित करती है. यह काम तो आप (कांग्रेस) करते थे।

ललन सिंह ने एक बेहद गंभीर उदाहरण देते हुए सदन को याद दिलाया कि कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता का क्या हाल था. उन्होंने कहा, 'एक मुख्य चुनाव आयुक्त थे आपके समय में. जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, आपने उन्हें राज्यसभा भेज दिया. इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री भी बना दिया गया. क्या यह संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान था? क्या यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता को प्रभावित करना नहीं था? आज आप हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा सरकार संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करती है और यही कारण है कि आज चुनाव प्रक्रिया इतनी सुदृढ़ है कि दुनिया भर में इसकी मिसाल दी जाती है।

नागरिकता और एसआईआर (SIR) पर भ्रम फैलाना बंद करें

चुनाव आयोग द्वारा कुछ जगहों पर एसआईआर कराने के फैसले और नागरिकता के मुद्दे पर भी ललन सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल भ्रम फैलाना रह गया है. ललन सिंह ने कहा, 'हम अगर देश के नागरिक हैं और चुनाव आयोग या सरकार हमसे नागरिकता का प्रमाण मांगती है, तो इसमें परेशानी क्या है? हमने भी अपना फॉर्म जमा किया. अगर आप सही हैं, तो डर कैसा?' उन्होंने बिहार का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि बिहार के महज दो जिलों में पांच लाख लोगों ने नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है. उन्होंने सवाल उठाया, ये पांच लाख लोग कौन थे? अगर सामान्य प्रक्रिया है तो ठीक, लेकिन अगर इसमें घुसपैठिए शामिल हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए. मनीष तिवारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, मनीष तिवारी तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. एसआईआर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है. अगर इसमें कुछ भी असंवैधानिक होता, तो वे सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्क रखते. संसद में इसे मुद्दा बनाकर केवल राजनीति की जा रही है।

'राहुल गांधी अब संविधान की किताब क्यों नहीं दिखाते?'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो पिछले कुछ समय से हर सभा में संविधान की लाल किताब दिखाते नजर आते थे, उन पर भी ललन सिंह ने तीखा व्यंग्य किया. उन्होंने कहा, 'पहले वे जहां जाते थे, संविधान की किताब साथ लेकर घूमते थे. लेकिन आजकल वो किताब नहीं दिखा रहे हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि अब वे खुद संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं. ललन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी की पूरी कार्यशैली ही संविधान और लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत है. उन्होंने कहा कि संविधान का सम्मान उसे हाथ में लेकर घूमने से नहीं, बल्कि उसके मूल्यों को मानने से होता है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत विरोधी पोस्ट करने के मामले में असम के प्रोफेसर को ज़मानत दी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर भारत विरोधी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए असम के एक कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर को सोमवार को जमानत दे दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि उन्हें दी गई राहत नौकरी पर उनकी बहाली का आधार नहीं बननी चाहिए. देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कोकराझार के सरकारी गोसाईगांव कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर जॉयनल आबेदीन की अपील पर सुनवाई करते हुए सशर्त ज़मानत का आदेश दिया. आबेदीन ने एक निचली अदालत और गुवाहाटी हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिनमें उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई थी. हालांकि, उनकी नौकरी पर बहाली का निर्देश देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा कि उनका नाम दो अन्य मामलों में भी दर्ज है, जिनमें उन पर छात्राओं से छेड़छाड़ करने और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष को अभी चार गवाहों की जांच करनी है और इसमें समय लगेगा. पीठ ने आदेश देते हुए कहा, 'अभियोजन को चार गवाहों की जांच करनी है. मुकदमे के निपटारे में समय लगेगा. याचिकाकर्ता पिछले छह महीनों से हिरासत में है. इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह जमानती मुचलका प्रस्तुत करे.' अदालत ने आगे स्पष्ट किया, 'इस आदेश को याचिकाकर्ता की पुनर्बहाली का आधार नहीं माना जाएगा और यह अत्यंत उचित होगा कि उसे बहाल न किया जाए, क्योंकि छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं.' गोसाईगांव कॉलेज में प्रोफेसर जॉयनल आबेदिन

पर आरोप है कि उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत-पाक तनाव के दौरान फेसबुक पर टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर लिखा था, 'हम पाकिस्तानी नागरिकों के भाइयों के साथ हैं और भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे.' मालूम हो कि उस दौरान ऑनलाइन पोस्ट के लिए लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. आबेदिन ने पहले कोकराझार की ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन आरोप तय होने की प्रक्रिया चल रही होने के कारण उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी. इसके बाद वे हाईकोर्ट गए जहां उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि, 'फेसबुक मैसेज को सीधे पढ़ने पर यह साफ है कि इस समय याचिकाकर्ता पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, अपने देश का नहीं. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के आर्टिकल 51ए (नागरिकों के मौलिक कर्तव्य) में निहित मूल कर्तव्यों का पालन नहीं किया.' पिछले महीने इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था, 'आपको सोशल मीडिया पर महिलाओं को परेशान करने और अश्लील टिप्पणियां करने की आदत है. आप एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति हैं और कॉलेज की छात्राओं के लिए खतरा हैं. आप किस तरह के प्रोफेसर हैं? आप 'प्रोफेसर' शब्द के लिए शर्म हैं. आपको कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'

संक्षिप्त ख़बरें

भागलपुर में स्कूल टीचर बच्चों से मंगवा रहे सीमेंट और सब्जी, ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बचे छात्र

शिक्षा सुधार के दावों के बीच बिहार के भागलपुर जिले से बेहद चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है. यहां पढ़ाई के समय छोटे-छोटे बच्चों से क्लास की जगह स्कूल के निर्माण कार्य के लिए सीमेंट और सब्जी मंगवाई जा रही है. छात्रों का आरोप है कि शिक्षिका ने 500-500 रुपये देकर 2 किमी दूर साईकल से सीमेंट लाने के लिए भेज दिया. मामला भागलपुर के गोराडीह प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय शेरगढ़ का है।

स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र ने बताया कि शिक्षिका गायत्री मैम ने 500 रुपये के दो नोट देकर बच्चों को मुरहन भेजा, जो स्कूल से लगभग 2 किलोमीटर दूर है. साथ ही कहा कि वहां से सीमेंट लेकर आओ.सीमेंट लाते वक्त मुरहन और शेरगढ़ के बीच पुल के पास बच्चे एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए. अगर कुछ पल की चूक होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. सवाल यह है कि ऐसी लापरवाही से यदि किसी बच्चे के साथ अनहोनी हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता?

यहां लापरवाही सिर्फ सीमेंट तक ही सीमित नहीं है. बच्चों ने बताया कि आलम सर सब्जी लाने के लिए भी छात्रों को भेजते हैं और कई बार फूलगोभी, आलू, प्याज जैसे सामान मंगवाए. एक छात्रा ने बताया कि प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार पहले भी कई बार आलू, गोभी, चना दाल सहित अन्य सामान मंगवाते थे।

आदेश जारी, फिर भी अनदेखी

इस मामले में जब गोराडीह प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) दिनेश कुमार दास से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. बड़ा सवाल यह है कि 26 सितंबर 2025 को BEO ने पत्रांक 582 के माध्यम से पहले ही पूरे प्रखंड के सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को स्पष्ट निर्देश दिया था।

इस निर्देश में लिखा था कि विद्यालय अवधि में कोई भी बच्चा कहीं भी अनियमित रूप से घूमता दिखा तो संबंधित शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी. इसके बावजूद शिक्षकों द्वारा खुलेआम इस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बच्चों से काम करवाया जा रहा है।

आगे क्या होगा?

घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोग और अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिक्षा पदाधिकारी इस बार कठोर कार्रवाई करेंगे, या फिर हमेशा की तरह केवल स्पष्टीकरण मांगकर मामला दबा दिया जाएगा. बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ को क्या सिर्फ औपचारिक कार्रवाई से निपटाया जाएगा।

हिन्दू अधिकारों पर फैसला देने वाले जज स्वामिनाथन पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव

●प्रियंका गांधी समेत 100 सांसदों की अर्जी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और इंडिया गठबंधन के 100 से ज्यादा सांसदों ने संसद में महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है. यह कदम जस्टिस स्वामीनाथन द्वारा दिए गए एक आदेश को लेकर उठाया जा रहा है. जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने 4 दिसंबर को एक मंदिर और दरगाह से जुड़े मामले में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला दिया था. उन्होंने सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के अधिकारियों को दूसरे पक्ष के विरोध के बावजूद दीपथून पर शाम 6 बजे तक दीपक जलाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद तमिलनाडु सरकार काफी भड़क गई थी और आदेश मानने से ही इनकार कर दिया।

मंदिर के अधिकारों की पुष्टि

विरोध का कारण इसकी सिकंदर बादशाह दरगाह से निकटता थी. इसके अलावा कार्तिकई दीपम आमतौर पर पहाड़ी पर स्थित उचिपेल्लैयार मंदिर के पास दीपा मंडपम पर जलाया जाता है. जस्टिस स्वामीनाथन ने इन सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया. अपने फैसले में न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि दीपथून पर दीप जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर कोई असर नहीं

होगा. लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि दीप नहीं जलाया गया तो इससे मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं. आरोप था कि मस्जिद के ट्रस्टी कथित तौर पर पहाड़ी के खाली हिस्सों पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं।

'मंदिर सतर्क रहें'

जज साहब ने कहा, 'भले ही यह परंपरा का मामला न हो,लेकिन दीपथून पर दीप जलाकर मंदिर का शीर्ष पर अधिकार जताना जरूरी है.' उन्होंने 1923 के एक फैसले का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मस्जिद ट्रस्टी यथास्थिति को भंग कर रहे हैं. मंदिर प्रबंधन को अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए चौकस रहना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने नहीं माना फैसला

जस्टिस स्वामीनाथन के आदेश को तमिलनाडु सरकार ने लागू करने से मना कर दिया. सरकार ने इसके पीछे कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया है. इसी आदेश को आधार बनाकर अब विपक्ष महाभियोग की तैयारी में है. तमिलनाडु सरकार इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

पिता नहीं, मां की जाति से बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट, सीजेआई सूर्यकांत के फैसले ने बदल दी सदियों पुरानी परंपरा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में एक नाबालिग बच्ची की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उसकी मां की जाति 'आदि द्रविड़' के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) प्रमाणपत्र जारी करने की मंजूरी दे दी. कोर्ट का यह फैसला दूरगामी असर डालने वाला माना जा रहा है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब शीर्ष अदालत के समक्ष पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें उस परंपरागत नियम को चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार बच्चे की जाति पिता की जाति के आधार पर तय की जाती रही है. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया, जिसमें पुडुचेरी की इस बच्ची को एससी जाति प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बच्ची को समय पर जाति प्रमाणपत्र नहीं मिला, तो उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है।

क्या बोले CJI सूर्यकांत?

हालांकि, सुप्रीम कोर्टकी बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस मामले में कानून से जुड़े बड़े प्रश्न को अभी खुला रख रही है. इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने नई बहस को जन्म दे दिया. उन्होंने कहा, 'समय के साथ जब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो फिर मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाणपत्र क्यों नहीं जारी किया जा सकता?' इस टिप्पणी को सामाजिक और कानूनी दृष्टि से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है. अगर भविष्य में यह सिद्धांत स्थापित होता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि अनुसूचित जाति की महिला और उच्च जाति के पुरुष की संतानें, भले ही वे उच्च जाति के सामाजिक माहौल में पली-बढ़ी हों, फिर भी वे एससी प्रमाणपत्र की हकदार हो सकती हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला पुडुचेरी की एक महिला से जुड़ा है, जिसने अपने तहसीलदार के पास आवेदन देकर अपने तीन बच्चों दो बेटियों और एक बेटे के लिए मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी. महिला ने अपने आवेदन में कहा था कि उसके माता-पिता और दादा-दादी सभी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से संबंध रखते हैं. उसने यह भी बताया कि शादी के बाद उसका पति उसके मायके में ही रहता रहा है. इस मामले में केंद्र सरकार के पुराने अधिसूचनाओं का भी जिक्र किया गया. 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचनाओं और गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण मुख्य रूप से पिता की जाति और उसके निवास स्थान के आधार पर किया

जाता रहा है।

पिता से ही तय होती थी बच्चों की जाति

सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस सिद्धांत को कई मामलों में स्वीकार कर चुका है कि बच्चे की जाति का निर्धारण सामान्य रूप से पिता की जाति के आधार पर होगा. वर्ष 2003 में 'पुनित राय बनाम दिनेश चौधरी' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण से जुड़े मामलों में जाति निर्धारण का निर्णायक आधार पिता की जाति होगी और परंपरागत हिंदू कानून के तहत संतान पिता से ही अपनी जाति प्राप्त करती है, न कि मां से।

हालांकि, 2012 में आए 'रमेशभाई दबाई नाइका बनाम गुजरात सरकार' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को कुछ हद तक लचीला बनाया था. उस फैसले में अदालत ने कहा था कि अंतरजातीय विवाह या आदिवासी और गैर-आदिवासी विवाह से जन्मे बच्चे की जाति का निर्धारण केवल पिता की जाति के आधार पर यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता. उस फैसले में यह भी कहा गया था कि ऐसे मामलों में यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि बच्चा पिता की जाति से जुड़ा होगा, लेकिन यह अनुमान अंतिम और अटल नहीं है।

पहले क्या था जाति निर्धारण का नियम?

सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में यह भी साफ किया था कि अगर बच्चा यह साबित कर दे कि उसका पालन-पोषण अनुसूचित जाति या जनजाति से जुड़ी मां के सामाजिक परिवेश में हुआ है और उसे जीवन में वही सामाजिक भेदभाव, अपमान और वंचनाएं झेलनी पड़ी हैं, जो उस समुदाय के अन्य लोगों को झेलनी पड़ती हैं, तो उसे उस समुदाय से संबंधित माना जा सकता है. अब ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के हितों को सर्वोपरि मानते हुए मां की जाति के आधार पर एससी प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जाति निर्धारण से जुड़े बड़े कानूनी सवालों पर अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा. इस फैसले के बाद देशभर में जाति प्रमाणपत्र, आरक्षण और अंतरजातीय विवाह से जुड़े अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ने की संभावना है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भविष्य में अदालत मां की जाति को भी निर्णायक आधार मानने की दिशा में जाती है, तो इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

PAK के टुकड़े करने में जिस मुस्लिम देश ने खुलकर दिया था भारत का साथ, अब वहीं जा रहे पीएम मोदी, होगी दिल की बात?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

इतिहास के पन्ने पलटें तो साल था 1971. भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी. पाकिस्तान के दो टुकड़े होने वाले थे और एक नया देश बांग्लादेश नक्शे पर उभर रहा था. उस वक्त दुनिया का कूटनीतिक माहौल भारत के खिलाफ था. अमेरिका अपना सातवां बेड़ा भेज रहा था और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के लगभग सभी ताकतवर देश सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन मजहब के नाम पर पाकिस्तान के साथ खड़े थे. लेकिन उस घने अंधेरे में एक चिराग था जो भारत के लिए जल रहा था. वह देश था ओमान. ओमान वह मुस्लिम देश था, जिसने अरब और इस्लामिक जगत के भारी दबाव को दरकिनार करते हुए, यूएन से लेकर हर वैश्विक मंच पर भारत का खुलकर समर्थन किया था. जब सब पाकिस्तान को बचाने में लगे थे, ओमान भारत की सच्चाई के साथ खड़ा था. अगले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी ओमान की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं. 17-18 दिसंबर का यह दौरा सिर्फ फाइलों पर दस्तखत करने का नहीं, बल्कि 54 साल पुरानी उस वफादारी को नमन करने का है।

1971 की वो कहानी, जो अक्सर नहीं सुनाई जाती

1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान ने खुद को 'इस्लाम के किले' के रूप में पेश किया था. अरब देशों पर भारी दबाव था कि वे भारत का बायकॉट करें. उस वक्त ओमान के सुल्तान कबूस बिन सईद ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया. उन्होंने साफ कर दिया कि ओमान, भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ नहीं जाएगा. सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देश सुल्तान कबूस से बेहद खफा हो गए थे. लेकिन सुल्तान अड़े रहे. उन्होंने न सिर्फ भारत का कूटनीतिक समर्थन किया, बल्कि अपनी बंदरगाहों और सुविधाओं के दरवाजे भी भारत के लिए खुले रखे. अब जब पीएम मोदी ओमान जा रहे हैं, तो वह एक तरह से उस दोस्ती का कर्ज चुकाने जा रहे हैं. ओमान भारत के लिए सिर्फ एक 'ट्रेडिंग पार्टनर' नहीं, बल्कि 'ऑल वेदर फ्रेंड' यानी हर मौसम का साथी है।

'दिल' के बाद अब 'डील' की बारी

1971 में ओमान ने दिल से साथ दिया था, 2025 में वह भारत की इकॉनमी को रफ्तार देने जा रहा है. पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत-ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर हस्ताक्षर होना लगभग तय है. इस समझौते के बाद भारतीय सामान जैसे कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी बिना किसी टैक्स के ओमान के बाजारों में बिक सकेगा. इससे चीन को झटका लगना तय है. ओमान रणनीतिक रूप से बहुत अहम जगह यानी अरब सागर और फारस की खाड़ी के मुहाने पर है. भारत वहां दुकम (Duqm) पोर्ट पर पहले से ही मौजूदगी दर्ज

करा चुका है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत वहां चीन के प्रभाव को कम करेगा और अपनी जड़ें जमाएगा।

'पुणे' वाला कनेक्शन और सुल्तान से याराना

कूटनीति में निजी रिश्तों का बहुत मोल होता है. ओमान के मौजूदा सुल्तान हैथम बिन तारिक के रगों में भारत से जुड़ी यादें हैं. सुल्तान हैथम के पिता ने भारत के पुणे शहर में पढ़ाई की थी. ओमान का शाही परिवार भारत को अपना दूसरा घर मानता है. पीएम मोदी और सुल्तान हैथम के बीच गजब का तालमेल है. पिछले साल जब सुल्तान भारत आए थे, तो यह उनकी पहली राजकीय यात्रा थी. अब पीएम मोदी का वहां जाना उस दोस्ती को और गहरा करेगा. ओमान में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं. पीएम मोदी जब उनसे मिलेंगे, तो यह संदेश जाएगा कि भारत अपने नागरिकों और अपने पुराने दोस्तों, दोनों का ख्याल रखता है।

जॉर्डन और इथियोपिया भी जाएंगे

पीएम मोदी की यह यात्रा सिर्फ ओमान तक सीमित नहीं है. वे जॉर्डन और इथियोपिया भी जा रहे हैं यह तीनों देश मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत के लिए बहुत मायने रखते हैं. जॉर्डन (97% मुस्लिम): तब और अब: 1971 में जॉर्डन पाकिस्तान के साथ था, लेकिन आज 2025 में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पीएम मोदी के करीबी दोस्त हैं. किंग अब्दुल्ला, जो पैगंबर साहब के वंशज माने जाते हैं, उनका पीएम मोदी का स्वागत करना इस्लामिक दुनिया में भारत की बदलती छवि का सबूत है. यह दौरा फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के संतुलन को दिखाएगा. इथियोपिया (34% मुस्लिम): पहला दौराः यह किसी भारतीय पीएम का पहला इथियोपिया दौरा होगा. वहां 4 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी है. भारत वहां अफ्रीका में अपनी पैठ बढ़ाने जा रहा है।

1971 की नींव पर 2025 का महल

पीएम मोदी का यह दौरा बताता है कि विदेश नीति में 'मेमोरी' कितनी अहम होती है. भारत ने नहीं भुलाया कि जब दुनिया खिलाफ थी, तब ओमान साथ था. ज जब ओमान के साथ ऐतिहासिक FTA होने जा रहा है, तो यह 1971 के उस बीज का फल है जिसे सुल्तान कबूस ने बोया था. ओमान में 'इकॉनमी' की बात होगी (FTA के जरिए), लेकिन उसकी बुनियाद में 'दिल' की वो बात होगी जो 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े होते वक्त ओमान ने भारत के कान में कही थी- हम तुम्हारे साथ हैं. यह दौरा उसी भरोसे को रीन्यू करने का है।

कर्मचारी मशीन नही- भारत की कार्य-संस्कृति पर बड़ी बहस

[क्या हम इंसान हैं या मशीन? राइट टू डिस्कनेक्ट का बड़ा सवाल]

[बच्चे की कहानी या बॉस का कॉल—कब तक चलेगी ये जद्दोजहद?]

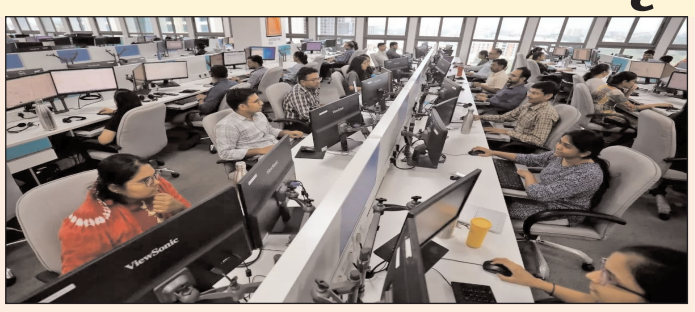

कल्पना कीजिए - रात के दस बज रहे हैं। घर में सुकून भरी रोशनी है, डिनर टेबल पर परिवार साथ बैठा है, और आपका बच्चा पहली बार स्कूल का किस्सा पूरे उत्साह से सुनाना शुरू करता है। तभी अचानक फोन की तेज़ रिंग उस खुशनुमा माहौल पर जैसे ब्रेक लगा देती है– 'सर, बस दो मिनट, ये प्रेज़ेंटेशन अपडेट कर दीजिए।' आप चेहरे पर मुस्कान सजाते हैं, पर भीतर कहीं गहरा दरार बन जाता है। अगले दस मिनट में खाना ठंडा हो जाता है, बच्चे की कहानी हवा में झूलती रह जाती है, और आपका मन एक बार फिर ऑफिस की अदृश्य जंजीरों में जकड़ जाता है। यह किसी एक परिवार की कहानी नहीं– पिछले दस सालों में भारत के करीब 60% से अधिक व्हाइट-कॉलर कर्मचारियों की कड़वी, रोज़ दोहराई जाने वाली सच्चाई है।

05 दिसम्बर को जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल-2025' रखा, तो भले ही सदन में तालियां नहीं बजीं सी, लेकिन देशभर के लाखों नौकरीपेशा लोगों के भीतर एक नई, चमकती उम्मीद ज़रूर जागी। यह बिल बिल्कुल साफ है: दफ़्तर के तय समय के बाद न कोई फोन ज़रूरी होगा, न ई-मेल, न वॉट्सऐप संदेश। जवाब न देना अब अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि सुरक्षित कानूनी अधिकार माना जाएगा। इतना ही नहीं, बिल में एक शक्तिशाली 'एम्प्लॉयी वेलफेयर अथॉरिटी' बनाने का भी प्रस्ताव है–एक ऐसी संस्था जो शिकायतें सुनेगी, नियम कड़ाई से लागू करेगी और ज़रूरत पड़ने पर जुर्माना लगाने की ताक़त भी रखेगी। यह बिल कोई अनसुना विचार नहीं है। पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन–दर्जनों यूरोपीय देशों में यह कानून पहले से लागू है। फ्रांस ने तो 2017 में ही 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया था। परिणाम चौंकाने वाले थे–बर्नआउट के मामले घटे, और उत्पादकता कम होने के बजाय बढ़ी, क्योंकि कर्मचारी अगले दिन ताज़गी और साफ़ दिमाग के साथ काम पर लौटते थे। इसके विपरीत, भारत में हम 70-80 घंटे काम करने की संस्कृति को ही उपलब्धि मानकर चलते रहे हैं। मगर डब्ल्यूएचओ और आईएलओ लंबे कार्य-घंटों के कारण दिल की बीमारी या स्ट्रोक से अपनी जान गंवाते हैं, और इनमें सबसे अधिक संख्या भारत और चीन के लोगों की है।

हमारे यहां हालात और भी भयावह हैं। एक हालिया सर्वे बताता है कि 60% से अधिक भारतीय कर्मचारी रात 11 बजे के बाद भी दफ़्तर के संदेशों का जवाब देने को मजबूर होते हैं। 70% से अधिक लोगों का साफ़ कहना है कि वे डर के कारण ऐसा करते हैं– 'जवाब न दिया तो बॉस नाखुश हो जाएगा, पदोन्नति रुक जाएगी, नौकरी पर असर पड़ जाएगा।' यही भय 'राइट टू डिस्कनेक्ट' को सिर्फ ज़रूरी नहीं, बल्कि अनिवार्य बनाता है। यह मात्र विश्राम का अधिकार नहीं–यह मानसिक संतुलन, व्यक्तिगत गरिमा और स्वस्थ जीवन का अधिकार है।

कुछ लोग तर्क देंगे– 'इससे तो काम ठप हो जाएगा!' पर सच इससे बिल्कुल उलट है। जब फ्रांस ने यह क़ानून लागू किया, तो कंपनियों ने खुद ही कार्य-संस्कृति को व्यवस्थित किया। मीटिंग्स छोटी हुईं, अनावश्यक संदेश बंद हुए, और प्राथमिकताएं स्पष्ट हुईं। भारत में भी यही बदलाव आएगा। क्योंकि जब कर्मचारी को भरोसा होगा कि रात दस बजे के बाद उसका फोन नहीं बजेगा, तब वह दिन के घंटों में ही दोगुनी एकाग्रता और ऊर्जा के साथ काम करेगा–बिना डर के, बिना थकान के। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद कडियाम काव्या ने इसी सत्र में महिला कर्मचारियों के लिए 'मेन्स्ट्रुअल लीव बिल' बिल पेश किया है, जो महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान 2 दिन की पेड लीव, रेस्ट सुविधाएं, साफ वॉशरूम और सैनिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर देता है। अब दो महत्वपूर्ण बिल साथ आए हैं–एक शरीर की थकान और मानसिक बोझ से बचाने वाला, दूसरा शरीर के दर्द और ज़रूरतों को समझने वाला। दोनों मिलकर यह साफ़ संदेश दे रहे हैं कि इंसान सिर्फ मशीन नहीं है। उसके पास नींद है, परिवार है, दर्द है, भावनाएँ हैं और सबसे बढ़कर–उसकी अपनी पूरी जिंदगी है।

ये प्राइवेट मेंबर बिल है। सही है, ज्यादातर प्राइवेट मेंबर बिल पारित नहीं होते। फिर भी इतिहास गवाह है–महिला आरक्षण बिल कभी प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ही रखा गया था, और समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त करने की मांग भी एक प्राइवेट बिल से हुई थी। कई विचार जो पहले असंभव, अव्यावहारिक या सिर्फ दूर की कल्पना माने जाते थे, वे जनता की सतत मांग, दबाव और सामूहिक आवाज़ से ही एक दिन वास्तविक कानून के रूप में आकार लेते हैं।

आज आवश्यकता है कि हम सब–कर्मचारी, यूनियन, मीडिया, सोशल मीडिया–मिलकर जोरदार आवाज़ उठाएं। अपने बॉस को नहीं, अपने सांसद को टैग करें। उनसे सीधे पूछें–क्या आप मेरे आराम और मेरी निज़ी ज़िंदगी के हक़ में हैं या नहीं? क्योंकि यह लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो शाम सात बजे के बाद अपने बच्चे की हंसी सुनना चाहता है, बिना यह डरे कि कहीं बॉस का मैसेज न आ जाए। यह हमारी गरिमा, हमारी खुशी और हमारी ज़िंदगी की लड़ाई है।

राइट टू डिस्कनेक्ट सिर्फ एक बिल नहीं, यह हमारी सभ्यता और जीवन के मूल्य का सवाल है। यह सीधे सवाल उठाता है–क्या हम इंसान को फिर से इंसान बनने का हक देंगे, या उसे हमेशा के लिए थकाऊ वर्किंग मशीन बनाकर रखेंगे? यह बिल केवल अधिकार की बात नहीं करता, यह हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार और हमारी मानसिक शांति का सम्मान मांगता है। उम्मीद है कि इस बार संसद साफ़ जवाब देगी–हां, तुम इंसान हो, मशीन नहीं। और वह दिन जब रात दस बजे फोन बजेगा, हम बिना किसी अपराधबोध या डर के उसे साइलेंट कर सकेंगे, अपने समय और अपने जीवन के मालिक बनकर। यह सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हमारी आज़ादी, हमारी गरिमा और हमारी खुशहाल जिंदगी की जीत होगी।

प्रो. आरके जैन

हवाई हड़ताल और यात्री

भारत में विमानन उद्योग निजी क्षेत्र से लेकर सार्वजनिक क्षेत्र तक में सैर करता रहा है मगर इससे पहले कभी ऐसी अफरा- तफरी का माहौल नहीं बना जैसा कि आजकल बना हुआ है। देश के सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों की भीड़ है जो अपने गन्तव्य तक जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मगर देश की निजी एयर लाइनों में से सबसे प्रमुख इंडिगो एयर लाइन ने हड़ताल कर रखी है जिसकी वजह से दूसरी एयर लाइनें मनमाना किराया वसूल रही हैं और हद यह हो गई है कि दिल्ली से मुम्बई तक की हवाई यात्रा का टिकट 60 हजार रुपए तक हो गया है। वास्तव में यह अराजकता का वातावरण है जिसकी तरफ भारत सरकार के नागरिक विमानन उड्डयन मन्त्रालय ने अब ध्यान दिया है। पिछले लगभग चार दिन से ऐसा ही माहौल बना हुआ है। देश में अब सरकार के हाथ में एक भी एयर लाइन नहीं है। घरेलू उड़ानों से लेकर विदेशी उड़ानों तक का कामकाज निजी एयर लाइनों के हाथ में है। इनमें से इंडिगो एयर लाइन के पास घरेलू उड़ानों का 65 प्रतिशत कारोबार है जबकि एयर इंडिया व अन्य विमानन कम्पनियों के पास शेष बाजार है। एयर इंडिया मुख्यतः विदेशी उड़ानों का कारोबार करती है। एयर इंडिया का निजीकरण हुए अभी कुछ वर्ष ही बीते हैं। इससे पहले यह सरकार के हाथ में थी मगर इसे टाटा समूह को बेच दिया गया। बाजार मूलक खुली अर्थव्यवस्था का नियम होता है कि इसमें उपभोक्ता मूलक बाजार संस्कृति को महत्व दिया जाता है अर्थात विभिन्न कम्पनियों के बीच जब प्रतियोगिता का माहौल बनता है तो उपभोक्ता को उत्पाद या सेवा प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध होती है। मगर बाजार पर यदि किसी एक कम्पनी का ही अधिपत्य हो जाता है तो वह बेखौफ होकर उपभोक्ताओं से मनमाना मूल्य वसूल करती है। भारत के विमानन क्षेत्र में आजकल यही हो रहा है और भारत का प्रतियोगिता आयोग (कम्पटीशन कमीशन) सोया हुआ पड़ा है। 1991 से पहले जब भारत मिश्रित अर्थव्यस्था में चल रहा था तो भी देश में एकाधिकर निरोधक आयोग(एमआरटीपीसी) था जो लगातार चौंकन्ना होकर किसी एक कम्पनी को बाजार पर एकाधिकार करने से रोकता था लेकिन खुली बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता आयोग द्वारा कलम हिलाने की शायद ही कोई घटना प्रकाश में आई हो जबकि बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में बाजार पर एकाधिकार जमाने की संभावनाएं भी सर्वाधिक बनी रहती हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान अब इस तरफ गया लगता है तभी उसने घरेलू उड़ानों का किराया नियत करने की तरफ जरूरी कदम उठाया है। अब 500 कि.मी. तक की हवाई दूरी तक के लिए अधिकतम किराया 7500 रुपए होगा जबकि 500 से 1000 किमी. दूरी के लिए 12 हजार होगा और एक हजार से डेढ़ हजार कि.मी. दूरी तक के लिए यह 15 हजार रुपए होगा। इससे ऊपर दूरी तक के लिए यह 18 हजार रुपए होगा। भारत में दिल्ली से चैन्नई की दूरी डेढ़ हजार किमी से ऊपर है। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी जिसकी वजह से सरकार को हरकत में आना पड़ा? इसका कारण इंडिगो एयर लाइन में पायलटों की हड़ताल थी। पायलटों ने यह हड़ताल अपनी सेवा शर्तों में बदलाव की वजह से की। इसकी वजह से एयर लाइन ने अपनी उड़ानों को रद्द करने का नया रिकार्ड बना डाला और इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई। जाहिर है इसकी वजह से पूरे देश के हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी बननी ही थी और यात्रियों को परेशानी होनी ही थी। अब जाकर सरकार ने इंडिगो एयर लाइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जवाब तलबी की है और पूछा है कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई क्यों न की जाये। कारण बताओ नोटिस जारी करके सरकार के उड्डयन मन्त्रालय ने अपनी जान बचाने की कोशिश ही की है जिससे नागरिकों का गुस्सा उस पर न उतर सके। मगर लोकतन्त्र में अन्तिम जिम्मेदारी सरकार की ही होती है जिससे वह अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। वर्तमान में उड्डयन मन्त्रालय का कार्यभार तेलगूदेशम पार्टी के श्री राम मोहन नायडू के पास है। यह पार्टी केन्द्र की मोदी सरकार में शामिल है परन्तु लोकतन्त्र में सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है जिससे सत्ता में बैठी कोई भी पार्टी अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। अतः केन्द्र सरकार को ही सामूहिक तरीके से यह सोचना होगा कि निजी विमानन कम्पनियों द्वारा किसी भी तरीके से उपभोक्ताओं या यात्रियों का शोषण न हो सके। इस बहाने सरकार यह भी जरूर सोचे कि देश की सभी विमानन कम्पनियों का निजीकरण करके कहीं उससे कोई चूक तो नहीं हो गई है। वास्तव में पिछली मनमोहन सरकार के दौरान ही एयर लाइनों के निजीकरण की आधारशिला रख दी गई थी। उस समय नागर विमानन मन्त्री राष्ट्रवादी कांग्रेस के श्री पटेल थे। उन्होंने एयर इंडिया व इंडियन एयर लाइनों का पहले विलीनीकरण किया और बाद में विलीनीकृत एयर इंडिया को घाटे में लाकर खड़ा कर दिया। श्री पटेल के कार्यकाल के दौरान लाभप्रद घरेलू व विदेशी हवाई रूट निजी कम्पनियों को आवंटित किये गये जिससे सरकारी एयर लाइन का घाटा बढ़ता ही गया और मोदी सरकार में स्थिति यह आ गई कि केवल दो निजी कम्पनियों का पूरे हवाई बाजार पर एकाधिकार हो गया। अतः इस स्थिति को भी बदलने की जरूरत है।

सीमापार साजिशों की जकड़न में कश्मीर घुसपैठ की नई आहट और भारत की सुदृढ़ सुरक्षा रणनीति

कश्मीर एक बार फिर उसी चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां सीमापार से होने वाली हलचलें, आतंकी नेटवर्क की गतिविधियां और पाकिस्तान समर्थित संगठनों का दबाव सुरक्षा तंत्र पर व्यापक असर डालने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में नियंत्रण रेखा के पार तेजी से बढ़ती गतिविधियों ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क होने पर मजबूर कर दिया है। विश्व के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले इस सीमाक्षेत्र में, इन दिनों घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ी हैं और खुफिया एजेंसियों के अनुसार सौ से अधिक आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं। इनकी संख्या 110 से 120 के बीच बताई जा रही है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अलग-अलग लॉन्चपैड से लगातार गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। इन संकेतों के बीच भारत ने भी अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया है। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, सेना की रणनीतिक तैनाती, बीएसएफ की उन्नत निगरानी और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय इन सभी ने मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जो किसी भी घुसपैठ के प्रयास को सीमापार ही विफल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीर के संवेदनशील भू-भाग में यह एक कठिन चुनौती तो है, लेकिन भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति और बहु-परत सुरक्षा संरचना इस खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम दिखाई दे रही हैं।

सीमा पर इन दिनों कड़ी निगरानी के साथ कई तकनीकी साधनों का उपयोग बढ़ाया गया है। नाइट विज़न कैमरे, हाई-टेक ड्रोन, अत्याधुनिक थर्मल इमेजिंग सिस्टम, ग्राउंड सेंसर, लेजर अलार्म और रियल-टाइम मॉनिटरिंग से जुड़े आधुनिक उपकरण जवानों को हर हरकत पर बारीकी से नजर रखने में सहायता प्रदान कर रहे हैं। कश्मीर घाटी के पहाड़ी और घने जंगलों वाले क्षेत्र में, जहां मौसम और भौगोलिक स्थिति सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनते रहे हैं, वहां भी तकनीक ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। इससे न केवल रात में होने वाली संभावित घुसपैठ की कोशिशें नाकाम हो रही हैं, बल्कि आतंकियों की आवाजाही से जुड़ी सूक्ष्म गतिविधियां भी तुरंत पकड़ में आ रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ ने वर्ष 2025 में अभी तक 118 पाकिस्तानी चौकियों को ध्वस्त किया है। यह संख्या इस बात का संकेत है कि सीमा पार की ओर से भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाली संरचनाओं को लगातार समाप्त किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार ने शून्य घुसपैठ का लक्ष्य निर्धारित किया है और बीएसएफ इस लक्ष्य को साधने के लिए संपूर्ण क्षमता, सामरिक समझ और निरंतर अभियान चला रही है। यह केवल सुरक्षा कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक संदेश है कि भारत किसी भी परिस्थिति में अपनी सीमाओं की अखंडता से समझौता नहीं करेगा।

भारत की सीमाओं के पार मौजूद आतंकी ढांचे को कई बार पाकिस्तान की ओर से प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन मिलता रहा है। नियंत्रण रेखा के पार बने लॉन्चपैड पर आतंकी गुटों की गतिविधियां पिछले कुछ हफ्तों में बढ़ी हैं। घुसपैठ के लिए अलग-अलग मार्गों की तलाश, खराब मौसम का लाभ उठाने की कोशिश और स्थानीय स्तर पर बने नेटवर्क को सक्रिय करने जैसे कई प्रयासों के बीच भारतीय सुरक्षा बलों ने भी गश्त बढ़ा दी है। गांवों, ऊंची चौकियों, कठिन पहाड़ी दर्रों और जंगलों में विशेष फील्ड यूनिट्स की तैनाती ने घुसपैठ की सभी संभावनाओं को सीमित कर दिया है। फोर्सेस को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी घुसपैठ की कोशिश को सीमा पार ही रोकना है। डीआईजी विक्रम कुंवर ने भी 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत कई महत्वपूर्ण लॉन्चपैड और पेड़-आधारित छिपने के ठिकानों को नष्ट करने की जानकारी दी है। यह अभियान उन आतंकियों के लिए बड़ा झटका है जो प्राकृतिक आड़ में छिपकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करते थे। पाकिस्तान समर्थित संगठनों द्वारा घाटी में आतंकी भेजने की साजिश नई नहीं, लेकिन भारत की रणनीति अब कहीं अधिक मजबूत, आक्रामक और तकनीकी रूप से दक्ष हो गई है। यही कारण है कि घुसपैठ के प्रयासों में तेजी आने के बावजूद सफल घुसपैठ की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

घाटी में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना केवल सीमापार निगरानी का मामला नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामरिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। इसमें सीमा पर निगरानी के साथ-साथ आतंरिक सुरक्षा, स्थानीय पुलिस की सतर्कता, खुफिया जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान और सेना-बीएसएफ-सीआरपीएफ व जम्मू-कश्मीर पुलिस के बीच समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बदलते सुरक्षा परिवेश और आतंकियों की नई रणनीतियों को देखते हुए भारत ने हर स्तर पर सुरक्षा ढांचा बहुस्तरीय बनाया है। यह केवल एक सैन्य आवश्यकता नहीं, बल्कि घाटी में शांति और विकास की निरंतर प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। कश्मीर के नागरिकों के सामने एक लंबा संघर्ष रहा है।आतंकवाद, अस्थिरता और सीमापार शत्रुता ने दशकों तक यहां की जनजीवन और विकास को प्रभावित किया। लेकिन हाल के वर्षों में स्थितियों में आए सकारात्मक बदलावों ने घाटी को नई दिशा दी है। इस दिशा को बनाए रखने के लिए घुसपैठ को रोकना सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद की जड़ें इसी घुसपैठ से मजबूत होती हैं। जितनी घुसपैठ कम होगी, उतना ही स्थानीय स्तर पर शांति का माहौल पनपेगा और विकास के मार्ग और अधिक खुलेंगे। सीमापार से आने वाली चुनौतियों का जवाब केवल सीमा पर तैनात जवानों की बहादुरी या तकनीक की क्षमता ही नहीं, बल्कि यह भारत की सामरिक नीति की परिपक्वता भी है। सरकार का जीरो-

इन्फिल्ट्रेशन का लक्ष्य इसी नीति का हिस्सा है।एक ऐसा लक्ष्य जो कठिन जरूर, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। इसी दिशा में बीएसएफ, सेना और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां एकमत होकर काम कर रही हैं। सीमापार हलचल चाहे जितनी तेज हो, भारत की सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए कई कदम आगे खड़ी दिखाई देती है।

घाटी में इन दिनों मौसम सर्द है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजरें पहले से ज्यादा गर्म और सतर्क हैं। हर हरकत पर नजर रखने वाला सुरक्षा कवच यह संदेश देता है कि कोई भी आतंकी, कोई भी संगठन और कोई भी बाहरी ताकत कश्मीर की शांति को भंग करने में सफल नहीं होगी। सीमापार जितनी हलचल बढ़ेगी, उतनी ही मजबूती से भारत अपनी सीमा की रक्षा करेगा। यही नई सुरक्षा नीति का केंद्र है।पहले चेतावनी, फिर निगरानी और अंत में निर्णायक कार्रवाई। कश्मीर के इस संवेदनशील समय में भारत ने अपनी तैयारी, इच्छाशक्ति और रणनीति के ज़रिए यह साफ कर दिया है कि अब घुसपैठ को केवल रोकना नहीं, बल्कि जड़ से समाप्त करना राष्ट्रीय लक्ष्य है। सीमा पर तैनात हर जवान, हर चौकी, हर कैमरा और हर तकनीकी व्यवस्था इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर काम कर रही है। पाकिस्तान समर्थित आतंकी भले साजिशें रचते रहें, लेकिन भारत की सीमाओं पर खड़ा सुरक्षा कवच पहले से कहीं अधिक मजबूत, सजग और अडिग है।

कांतिलाल मांडोत

संपादकीय

भ्रष्टाचार का वैश्विक संकट और हमारी नैतिक जिम्मेदारी

हर वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस केवल एक औपचारिक स्मरण दिवस नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए उस चुनौती की ओर संकेत करता है जो राष्ट्रों की प्रगति, सामाजिक न्याय और नैतिक मूल्यों को भीतर से क्षीण करती रहती है। यह दिन 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी अभिसमय की याद दिलाता है, जिसने भ्रष्टाचार को किसी एक देश, संस्था या समाज की समस्या न मानकर एक वैश्विक संकट के रूप में स्वीकार करने का साहस दिखाया। दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचनाओं में फैलती अनियमितताओं और सत्ता-लाभ के रोग ने जिस प्रकार राष्ट्रों की क्षमताओं को कमजोर किया है, वह इस अभिसमय की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। भ्रष्टाचार विकास का सबसे बड़ा अवरोध इसलिए भी है कि यह राज्य के संसाधनों और संरचनाओं को उस स्थान तक पहुँचने से रोक देता है जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए जनता के जीवन में सुधार, समान अवसरों की उपलब्धता और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण।

आज विश्व बैंक की रिपोर्ट्स और वैश्विक संगठनों के आकलन स्पष्ट बताते हैं कि भ्रष्टाचार प्रतिवर्ष खरबों डॉलर को निगल जाता है। रिश्वत, घोटाले, फर्जी ठेके, लाभ हस्तांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे रूपों में यह आर्थिक अपराध अब किसी सीमा में बँधा नहीं रहा। सबसे अधिक पीड़ा की बात यह है कि इसका दुष्प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास आवाज़ कमजोर है, संसाधन सीमित हैं और जिनकी जीवन-गुणवत्ता शासन की ईमानदार नीतियों पर निर्भर करती है। विकासशील देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जनकल्याण कार्यक्रमों के विफल होने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, पर भ्रष्टाचार उन सभी का साझा और सबसे निर्दयी दोषी है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में भ्रष्टाचार की समस्या और भी जटिल हो जाती है क्योंकि यहाँ शासन जनता की भागीदारी पर आधारित है। लोकतंत्र की आत्मा ही पारदर्शिता और जवाबदेही है, किंतु जब व्यवस्थाएँ राजनीति, नौकरशाही, ठेकों और व्यावसायिक हितों के दबाव में उलझने लगती हैं, तब सार्वजनिक विश्वास टूटता है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने नीतिगत सुधारों, प्रशासनिक पारदर्शिता और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने के अनेक प्रयास किए। लोकपाल, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम जैसे कदम निश्चित रूप से परिवर्तन की दिशा में महत्त्वपूर्ण हैं। डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार आधारित सत्यापन ने लाभार्थी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई है। फिर भी यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें सामाजिक और राजनीतिक ताने-बाने में अभी भी गहरी हैं।

समस्या का सबसे कठिन पक्ष यह है कि भ्रष्टाचार केवल कानून से नियंत्रित होने वाली गतिविधि नहीं, बल्कि मनोवृत्ति है। जब समाज में लाभ-प्रथम सोच मूल्य-आधारित जीवन को पीछे धकेल देती है, जब सुविधा पाने के लिए शॉर्टकट सामान्य व्यवहार बन जाता है, और जब शक्ति का उपयोग सेवा की जगह पकड़ मजबूत करने में किया जाने लगता है तभी भ्रष्टाचार एक आदत बन जाता है। भारतीय परंपरा में सत्य, धर्म और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 'सत्यमेव जयते' केवल मुहर पर अंकित वाक्य नहीं, बल्कि शासन की मूल आत्मा है। गांधी ने सत्य को राजनीति का केंद्र बताया, कबीर ने मानव चरित्र की पवित्रता को श्रेष्ठता का पैमाना माना और तुलसी ने मर्यादा को जीवन-संयम का आधार कहा। ऐसे सांस्कृतिक धरोहर वाले समाज में भ्रष्टाचार का फैलना यह दर्शाता है कि संकट केवल संस्थानों का नहीं, बल्कि मनुष्य की नैतिकता का भी है। यदि पारिवारिक और सामाजिक परिवेश बच्चों और युवाओं में ईमानदारी के संस्कार विकसित नहीं करता, तो प्रशासनिक सुधार चाहे जितने सक्षम हों, वे अधूरे ही रहेंगे।

युवा पीढ़ी इस परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन बन सकती है। शिक्षा संस्थानों में नैतिक शिक्षा को केवल एक विषय की तरह नहीं, बल्कि जीवन-दृष्टि की तरह समझाया जाना चाहिए। युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि पारदर्शिता की मांग केवल आलोचना नहीं, बल्कि निर्माण का मार्ग है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म आज आवाज़ को ताकत देते हैं, पर उनका उपयोग केवल सनसनी या राजनीतिक शोर के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता और सुधार के लिए होना चाहिए। सच यह है कि परिवर्तन लाने का साहस अक्सर युवाओं में ही होता है और यदि वही भ्रष्टाचार-विरोधी सोच के वाहक बनें, तो आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर शासन-प्रणाली विरासत में मिल सकती है।

भ्रष्टाचार का चरित्र आज अंतरराष्ट्रीय हो चुका है। एक देश में हुए अपराध का पैसा दूसरे देशों की टैक्स हैवन अर्थव्यवस्थाओं में सुरक्षित हो जाता है। कॉरपोरेट लॉबिंग, डिजिटल वित्तीय नेटवर्क, सीमा-पार निवेश और व्यापारिक गठजोड़ों ने भ्रष्टाचार को एक वैश्विक उद्योग का रूप दे दिया है। ऐसे में दुनिया के देशों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान, आपराधिक प्रत्यर्पण और वित्तीय पारदर्शिता के लिए साझा मंच अनिवार्य हो गया है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, इंटरपोल और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force) जैसी संस्थाएँ मिलकर जिस सहयोगी ढांचे की वकालत कर रही हैं, वह इस लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक हो सकता है। कोई भी देश यह मानकर नहीं चल सकता कि वह अकेले इस संकट से निपट सकता है।

अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हमें यही सोचने का अवसर देता है कि ईमानदारी किसी और से अपेक्षित गुण नहीं, बल्कि स्वयं से शुरू की जाने वाली प्रक्रिया है। समाज के हर स्तर पर, घर से लेकर कार्यालय तक, शिक्षालय से लेकर प्रशासन तक, हम जितना ईमानदारी को व्यवहार में उतारेंगे, उतना ही भ्रष्टाचार का दायरा सिमटेगा। कानून और संस्थाएँ अपनी जगह महत्त्वपूर्ण हैं, पर वे तभी प्रभावी हो सकती हैं जब नागरिक स्वयं नैतिकता के प्रति प्रतिबद्ध हों।

स्वच्छ, पारदर्शी और न्यायपूर्ण समाज किसी एक सरकार के प्रयासों का परिणाम नहीं होता; यह नागरिकों की सामूहिक चेतना और निरंतर ईमानदार आचरण से बनता है। विकास तभी टिकाऊ है जब वह सत्य और न्याय की नींव पर खड़ा हो। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यह स्मरण कराता है कि दुनिया तभी आगे बढ़ सकती है जब ईमानदारी उसका आधार बने और यह आधार किसी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर निर्मित होता है।

महेन्द्र तिवारी

ताइवान को दूसरा यूक्रेन बनाने की अमेरिकी तैयारी और भारतीय दृष्टिकोण की अहमियत

दुनिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ वैश्विक शक्ति-संतुलन तेजी से बदल रहा है, और इसी शक्ति संघर्ष के केंद्र में ताइवान खड़ा है, जिसे अमेरिका और चीन के बीच तनाव की धुरी माना जाने लगा है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने विश्व को यह दिखा दिया है कि महाशक्तियों के भू-राजनीतिक खेल में छोटे देश किस तरह तबाह हो जाते हैं, और अब यही खतरा ताइवान के सिर पर मंडरा रहा है। अमेरिका द्वारा ताइवान को लगातार सैन्य, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन को रूस के विरुद्ध भड़काया गया था। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जिस देश का समर्थन करता है, वह अंततः संकट की कगार पर पहुंच जाता है और अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ तालिबानी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के समय अमेरिका ने रातों-रात सेना वापस बुलाकर अफगानिस्तान को अराजकता और खूनी सत्ता-परिवर्तन के हवाले कर दिया। यूक्रेन को रूस के विरुद्ध खड़ा करने का परिणाम दुनिया देख चुकी है–अरबों का नुकसान, लाखों निर्दोष लोगों की मौतें, शहरों का मलबा, और युद्ध का अंत आज तक नहीं। अमेरिका और नाटो के राष्ट्र बाहर बैठकर तमाशबीन बने रहे, हथियार बेचे, राजनीति चमकाई, पर जमीन पर कोई निर्णायक समर्थन नहीं दिया। अब ताइवान पर यही खेल दोहराया जा रहा है।

अमेरिका द्वारा ताइवान की संप्रभुता जैसी संवेदनशील विषय पर खुला समर्थन, 'रणनीतिक अस्पष्टता' की नीति के बजाय स्पष्ट हस्तक्षेप का संकेत देता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा, चीन की कड़ी चेतावनियों के बावजूद, अमेरिका की उस रणनीति को दर्शाती है जो चीन-विरोधी शक्ति संतुलन बनाने के लिए ताइवान को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। चीन ने इस यात्रा को अपनी संप्रभुता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बताया और सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दी, उसकी सेना ने ताइवान के चारों ओर लाइव-फायर सैन्य अभ्यास का ऐलान करते हुए युद्ध-स्तरीय तैयारी शुरू कर दी। नैंसी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर कहा कि 23 मिलियन ताइवानी लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। ऐसे बयान यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले अमेरिका द्वारा दिए गए बयानों जैसे ही प्रतीत होते हैं, जहाँ यूक्रेन को 'पूर्ण समर्थन' का आश्वासन दिया गया, पर युद्ध शुरू होते ही अमेरिका ने सुरक्षित दूरी बना ली।

चीन 20 वर्ष पहले वाला देश नहीं। सैन्य, आर्थिक और सामरिक क्षमता में वह विश्व की शीर्ष तीन शक्तियों में है। रूस-यूक्रेन युद्ध में उसने रूस का समर्थन कर यह संकेत

संक्षिप्त खबरें

संगम की लहरों पर प्रयागराज में बनेगा भव्य रामसेतु

मिंटो पार्क से नैनी तक 1200 मीटर लंबा सेतु, 258 करोड़ में बनेगा नया मार्ग।

प्रयागराज। तीर्थ, इतिहास और आस्था की मिट्टी से सजी संगमनगरी अब एक और अविस्मरणीय अध्याय की देहरी पर खड़ी है। यमुना की शांत लहरों पर एक ऐसा सेतु आकार लेने जा रहा है, जो सिर्फ लोहे-कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि श्रद्धा, परंपरा और समय के बीच संवाद का एक जीवंत प्रतीक बनेगा। करीब 1200 मीटर लंबा और 5 से 7 मीटर चौड़ा यह रामसेतु संगम तट पर आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों के अनुभव को नई ऊंचाई देगा। यह सेतु उस आस्था का साक्षी बनेगा, जहां हर कदम यात्रा नहीं, दर्शन और अनुभूति लेकर चलता है। करीब 258 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह पवित्र सेतु मदन मोहन मालवीय पार्क (मिंटो पार्क) को नैनी स्थित शिवालय पार्क से जोड़ेगा। सदियों से इन दोनों छोरों पर खड़े श्रद्धालु घाटों तक पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब उनके कदमों के बीच यह सेतु एक स्थायी और पवित्र मार्ग बनाएगा। सेतु निगम ने परियोजना की डीपीआर शासन को सौंप दी है, जिससे यह सपना अब कागज़ से निकलकर जमीन पर उतरने लगा है। दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा डिजाइन तैयार की जा रही है और प्रस्तावित योजना के अनुसार चार वर्षों के भीतर रामसेतु पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह सेतु प्रयागराज की पहचान में एक नया आयाम जोड़ेगा– एक ऐसा मार्ग, जहां हर कदम भक्ति की अनुभूति देगा और हर दिशा संगम की आध्यात्मिकता को महसूस कराएगी।

विप्र महासंघ के मीडिया प्रभारी बने महेश प्रसाद त्रिपाठी

प्रयागराज। राष्ट्रीय विप्र महासंघ संगठन ब्राह्मण हिताय, ब्राह्मण सुखाय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार चौबे ने कहा कि यह संगठन ब्राह्मण समाज को संगठित कर उनके हितों को साधने के लिए अभियान चलाया गया है। छिवकी रेलवे स्टेशन स्थित गदामाधव मंदिर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय विप्र महासंघ अराजनैतिक ब्राह्मण हिताय व ब्राह्मण सुखाय, सनातन धर्म एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार से सम्बन्धित निःशुल्क और निस्वार्थ संगठन है। बदलते परिवेश में संगठन के अहमियत पर आधारित अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय ब्राह्मण समाज ही सबके निशाने पर है।अन्य समाज के लोगों द्वारा भला-बुरा कहने से कोई गुरेज नहीं किया जाता। सनातन एवं सनातनियों पर चोट की जाती है। ब्राह्मण अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए निरन्तर जूझता रहा है। यह संगठन ब्राह्मण समाज को संगठित कर न्याय हित के लिए यह साबित करना चाहता है कि हम परशुराम के वंशज हैं। समय आने पर फरसा भी धारण कर सकते हैं। मीडिया प्रभारी महेश प्रसाद त्रिपाठी ने कहा कि हालांकि, ब्राह्मण समाज को एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक रूप से काम करने को लेकर तराजू में मेढक तौलने जैसा है। सहमींडिया प्रभारी बालेन्द्र कुमार बलराम ने कहा कि हमारा संगठन राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखता, धन सम्बन्धी कोई लेनदेन भी नहीं किया जाता। हम ब्राह्मण समाज का आवाहन करते हुए कहना चाहते हैं कि संगठन में संगठित होकर लगन से ब्राह्मण समाज का उत्थान करने के प्रयासों में जुट जाएं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रमोद मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माधव प्रसाद शुक्ल, जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

56 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 40 बीघा जमीन पर बिना नक्शा पास कराए हो रही थी बिक्री

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में जिलाधिकारी राजा गणपति आर की सख्ती के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आ गया। सदर तहसील खैराबाद क्षेत्र के विष्णु नगर स्थित तारा सिटी में करीब 40 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सोमवार दोपहर को बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासनिक टीम ने तीन बुलडोजरों की मदद से खेत में किए गए निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त करा दिया इस दौरान प्लाटिंग के लिए बनाए गए आलीशान गेट, चारदीवारी और ईटों से किए गए अन्य निर्माण को भी तोड़ दिया गया प्रशासन के अनुसार करीब 56 करोड़ रुपए मूल्य की इस जमीन पर बिना किसी मानक और अनुमति के प्लाटिंग की जा रही थी भूमि स्वामी जैन द्वारा प्लाटिंग के लिए कोई भी नक्शा पास नहीं कराया गया था और न ही संबंधित विभागों से अनुमति ली गई थी इसके बावजूद बड़े पैमाने पर प्लाट काटकर बेचने की तैयारी चल रही थी।

जांच में यह भी सामने आया कि धारा 80 का सहारा लेकर राजस्व को चूना लगाते हुए प्लाटिंग की जा रही थी मामले की शिकायत जिलाधिकारी तक पहुंचने के बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद तहसील प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार वसुंधरा त्रिपाठी और महेंद्र तिवारी ने किया। उनके साथ लेखपालों की टीम और खैराबाद पुलिस बल भी मौजूद रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई प्रशासन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना मानचित्र पास कराए और नियमों का पालन किए बिना की जाने वाली किसी भी अवैध प्लाटिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी!!

लेखपाल ने शिकायतकर्ता की मिलीभगत से किसान की गेहूं की फसल को जोतवाया

● पीड़ित किसान ने डीएम से लगाई न्याय की गुहार, दोषियों पर कार्रवाई की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

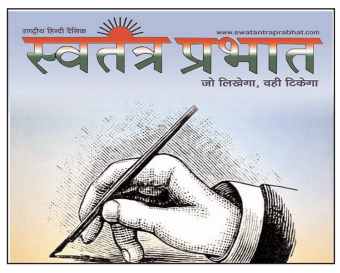

सीतापुर (ब्यूरो) खैराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बन्नीशाहपुर में एक किसान की खड़ी गेहूं की फसल को क्षेत्रीय लेखपाल और शिकायतकर्ता की कथित मिलीभगत से ट्रैक्टर चलवाकर जोत दिए जाने का गंभीर मामला उजागर हुआ है। पीड़ित किसान साजिद खां व शिवराम ने जिलाधिकारी सीतापुर को प्रार्थनापत्र देकर दोनों पर मनमानी, दबंगई और सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार उसकी कृषि भूमि गाटा संख्या 754-क जो संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, जिस पर 7 दिसम्बर को शाम करीब 2:50 बजे, बिना किसी पैमाइश और बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के, लेखपाल आलोक मिश्रा ने शिकायतकर्ता अजय पाल जायसवाल के कहने पर खड़ी गेहूं की फसल ट्रैक्टर से नष्ट करा दी।

किसान व ग्रामीणों के विरोध के बावजूद लेखपाल ने न सुनवाई की और न नाप-जोख कराई। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल ने उसे धमकी देते हुए कहा– ज्यादा बोलोगे तो एफआईआर लिखाकर जेल भिजवा दूँगा। किसान का साफ कहना है कि उसके कब्जे की जमीन पर न कोई अवैध निर्माण था, न कोई विवाद, फिर भी उसकी मेहनत पर कुठाराघात किया गया। पीड़ितों ने जिलाधिकारी से दोनों विपक्षियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, नुकसान की भरपाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

'अविवाहित बेटी भी पिता से मांग सकती है गुजारा भत्ता, दूसरी शादी या नौकरी नहीं करने तक पत्नी भी हकदार'

नई दिल्ली। अविवाहित बेटी व उसकी मां को गुजारा भत्ता देने के संबंधी पारिवारिक अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली व्यक्ति की याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि एक बालिग हिंदू बेटी हिंदू दत्तक ग्रहण एवं रखरखाव अधिनियम की धारा- 20 के तहत अपने पिता से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है, जब तक वह अविवाहित है और अपनी कमाई से अपना गुजारा नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि बालिग अविवाहित बेटी सीआरपीसी की धारा-125 के तहत पिता से गुजारा भत्ता मांगने के लिए मां के साथ मिलकर संयुक्त आवेदन दाखिल कर सकती है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए पिता की याचिका खारिज कर दी। पारिवारिक अदालत ने बेटी और मां दोनों को अंतरिम गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 45,000 रुपये देने का आदेश दिया गया था। दोनों ने मिलकर गुजारा भत्ता मांगने के लिए एक आवेदन दाखिल किया था। पारिवारिक अदालत ने कहा था कि पत्नी तब तक गुजाजा भत्ता पाने की हकदार होगी, जब तक वह दूसरी शादी नहीं कर लेती या उसे कोई नौकरी नहीं मिल जाती।

लखनऊ में गर्लफ्रेंड ने लिव-इन-पार्टनर को मार डाला, खुद पुलिस को फोन कर जानकारी दी

लखनऊ में लिव-इन पार्टनर की हत्या

बेटियों के सामने महिला ने किया कत्ल

लखनऊ। लखनऊ में एक गर्लफ्रेंड ने अपने लिव-इन-पार्टनर की हत्या कर दी। महिला ने अपनी दो बेटियों के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। अयोध्या रोड की शिवम ग्रीन सिटी में सोमवार की सुबह लिव इन में रहने वाली महिला ने अपनी दो बेटियों के सामने 33 वर्षीय बॉयफ्रेंड सूर्य प्रताप सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को खुद ही फोन कर हत्या करने की सूचना भी दी। आनन फानन में पहुंची पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए हैं। शव पोस्टमार्टम को भेजने के बाद महिला को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

रहीमाबाद में मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद। मिशन शक्ति फेस-5 के तहत थाना रहीमाबाद पुलिस ने सोमवार दोपहर को जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान अहमदाबाद कटौली स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल की छात्राओं के लिए आयोजित किया गया था।

एंटी रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम ने छात्राओं को महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी। इनमें 1098, 1090, 181, 1076, 1930, 101, 112, 102 और 108 शामिल थे। इस दौरान छात्राओं को संबंधित पम्पलेट भी वितरित किए गए।कार्यक्रम में एंटी रोमियो टीम, पिंक बूथ, पिंक मोबाइल और महिला शक्ति केंद्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी साझा की गई। इसके अतिरिक्त, छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति सचेत किया गया और उनसे बचाव के उपायों के लिए टोल फ्री नंबर 1930 के बारे में बताया गया। नए कानूनों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पुलिस टीम ने विद्यालय के छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्हें बिना हेलमेट वाहन न चलाने, तीन सवारी से बचने और अत्यधिक गति से वाहन न चलाने की सलाह दी गई।कार्यक्रम में प्रबंधक मोहम्मद कफील,प्रधानाचार्य कुसुमलता और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। अभियान के दौरान, अपनी- अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।कार्यक्रम में इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुणायक, उपनिरीक्षक अनिरुद्ध कुमार मिश्र, उपनिरीक्षक अनिल कुमार वर्मा, कांस्टेबल मनु कुमार और महिला कांस्टेबल प्रियंका डागर सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

पीएसी बैरियल से टकराई बाइक दो लोगों की हुई मौत घर में मचा कोहराम, शराब के नशें में वाहन चलाने की आशंका

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई देर रात तेज रफ्तार बाइक पीएसी में सड़क पर लगे बैरियर से टकरा गई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल और बाइक के परखच्चे उड़ गए। एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया वहीं मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के 27 बटालियन पीएसी मार्ग का है। जानकारी के अनुसार हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ। यहां 11 बटालियन आयुध भंडार के सामने सड़क पर लगे बैरियर से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बैरियर से टकराने के बाद करीब 10 फिट दूर जाकर गिरी। आसपास मौजूद लोगों ने हादसा होते ही पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। हादसे में बाइक पर सवार हसीमुद्दीन पुत्र रिजवान अहमद निवासी करसेवरा थाना तालगांव और मनीराम पुत्र मैकू निवासी पलिया कला थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर उम्र करीब 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए दोनों युवक सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। मौके पर पहुंची चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी ने हमराही के साथ 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया।

जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, मृतक हसीमुद्दीन और मनीराम के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां मातम पसरा रहा पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसा तेज रफ्तार और बैरियर से टकराने के कारण हुआ है वही आशंका व्यक्त की जा रही है दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे। फिलहाल पुलिस की मामले की जांच की जा रही है!!

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए की मौत की वजह साफ़ नहीं, मृत तेंदुए का विसरा बरेली लैब गया भेजा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में शनिवार को खेतों के समीप मृत मिले तेंदुए की मौत की गुत्थी अभी तक पूरी तरह सुलझ नहीं सकी है पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई है जिससे वन विभाग की चिंता बढ़ गई है। अब तेंदुए की मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए वन विभाग ने उसका विसरा आईवीआरआई बरेली लैब भेज दिया है वन विभाग के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तेंदुए के शरीर के अंदरूनी हिस्सों में खून का बहाव पाया गया है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि यह स्थिति किस कारण से उत्पन्न हुई। इसी वजह से डॉक्टरों ने फिलहाल किसी एक कारण पर मुहर नहीं लगाई है। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण बीमारी ही माना जा रहा है लेकिन इसकी पुष्टि विसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि मृत तेंदुआ नर था और उसकी उम्र करीब 6 वर्ष के आसपास आंकी गई है उन्होंने जानकारी दी कि पोस्टमॉर्टम के दौरान तेंदुए के दांत और नाखून पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं इसके अलावा तेंदुए के शरीर के बाहरी हिस्सों पर किसी प्रकार के चोट, संघर्ष या हमले के निशान नहीं मिले हैं जिससे शिकार या आपसी संघर्ष की आशंका फिलहाल कम मानी जा रही है।

गौरतलब है कि शनिवार शाम करीब 5 बजे हरगांव के अटरा स्थित शारदा सहायक नदी के समीप खेतों के पास ग्रामीणों ने तेंदुए का शव पड़ा देखा था जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर रविवार को दो डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमॉर्टम कराया गया शुरुआत में बीमारी की आशंका जताई गई थी लेकिन रिपोर्ट में भी मौत की ठोस वजह सामने न आने से मामले को लेकर संशय बरकरार है फिलहाल वन विभाग विसरा जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है अधिकारियों का कहना है कि लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही तेंदुए की मौत के असली कारण का खुलासा हो सकेगा!

तेज़ रफ़्तार का कहर कार ने बच्ची को मारी टक्कर गंभीर रूप से घायल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में सीतापुर मार्ग पर सोमवार दोपहर को सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई हादसा ग्राम नेवादा के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बालिका को टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्राम नेवादा निवासी राजिक के घर रिश्तेदारी में 5 वर्षीय बालिका आई हुई थी। सोमवार को वह घर के बाहर सड़क किनारे अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह अचानक सड़क पार करने के लिए दौड़ पड़ी तभी सीतापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बालिका सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना होते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। उधर, कार चालक बच्ची को टक्कर मारकर वाहन सहित मौके से फरार हो गया लोगों में चालक की लापरवाही को लेकर आक्रोश भी देखा गया। कार की रफ्तार और हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। परिजन घायल बालिका को आनन-फानन में इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बालिका को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं, हालांकि उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। पुलिस का कहना है कि फरार कार चालक की तलाश की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है पुलिस ने वाहन की पहचान कर जल्द आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है!!

मेरठ में तेज रफ्तार का कहर...डिवाइडर से कूदकर स्कॉर्पियो से टकराई ब्रेजा कार, दो की मौत; 7 घायल

मेरठ। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एनएच-09 बछलौता गांव के सामने स्थित शिवा ढाबे के पास तेज रफ्तार ब्रेजा कार डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ जा रही स्कॉर्पियो से जा टकराई और पलट गई। दुर्घटना में ब्रेजा कार सवार दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इसी कार में सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से दो घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार चार लोग भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से विभिन्न अस्पतालों में घायलों को भर्ती कराया है। जहां उनका उपचार चल रहा है। मेरठ जिले के परतापुर थाना क्षेत्र के सोलाना कांशी गांव निवासी 17 वर्षीय शाकिब गांव निवासी अपने दोस्त 21 वर्षीय गुलजार, 22 वर्षीय मुजीब, 22 वर्षीय मौज्जम व अपने बहनोई मेरठ के लिसाड़ी गांव निवासी इकरार के साथ शनिवार देर रात करीब 12.30 बजे ब्रेजा कार में सवार होकर मेरठ से थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के एनएच-09 स्थित राजाजी हवेली ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे थे। सभी लोग कार में बैठे थे और शाकिब के बहनोई इकरार कार चला रहे थे।

गौहनिया-करछना मार्गः सफर में, रोज मौत से मुठभेड़

● प्रशासन की खामोशी सेजिले का मुख्य रास्ता भय का प्रतीक बन गया।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

प्रयागराज। यमुनापार गौहनिंया से करछना सम्पर्क मार्ग सुबह का उजाला धीरे-धीरे फैल रहा था। लोग अपने काम-काज के लिए निकलने लगे थे- किसी को बाज़ार जाना था, किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ना था, तो कोई करछना की ओर काम पर जा रहा था। लेकिन जैसे ही वाहन गौहनिया से करछना जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर चढ़ते हैं, दिल दहल जाता है। यह कोई गांव की पगडंडी नहीं, बल्कि वह प्रमुख सड़क है जो करछना को प्रयागराज शहर से जोड़ती है और जहां से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है मानो सड़क नहीं, मौत का खड्ड बना दिया गया हो। कहीं एक फीट गहरा गड्ढा, कहीं सड़क पूरी तरह टूटी, कहीं दलदली गड्ढा–हर मोड़, हर कदम खतरे से भरा हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह मार्ग पहले कितना सुगम था, लेकिन अब किसी भी वाहन का यहां से सकुशल निकल जाना किसी चमत्कार से कम नहीं। गाड़ियों के पहिए गड्ढों में फंसते ही उछल जाते हैं, बाइक सवार गिरने से बचने के लिए लड़खड़ा जाते हैं और चारपहिया वाहन पलटने तक की स्थिति में आ जाते हैं।

रोजाना होने वाली इन परेशानियों ने लोगों के दिल में डर बैठा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्रयागराज जिला प्रशासन की नजर इस मार्ग पर नहीं जाती? शिकायतें की गई, तस्वीरें भेजी गई, सोशल मीडिया पर आवाज उठाई गई, लेकिन न तो लोक निर्माण विभाग (PWD), न जिला प्रशासन, न DM ऑफिस और न ही यातायात पुलिस–किसी ने भी इस सड़क की सुध लेने की ज़हमत नहीं उठाई।

लोगों का कहना है कि यह जिले की महत्वपूर्ण सड़क है, जहां से करछना जाने वाले अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी, छात्र और आम जनता रोजाना गुजरती है। फिर भी इस मार्ग की उपेक्षा समझ से परे है। पिछले कुछ दिनों में इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक युवक काम पर जाते समय गहरे गड्ढे में बाइक सहित गिर पड़ा। एक महिला स्कूटी का संतुलन बिगड़ने से सड़क पर फिसल गई। दूसरी ओर, कई कारों के टायर फट चुके हैं और एंबुलेंस तक इस रास्ते में फंसकर देर से पहुंचती हैं।

रात के समय यह मार्ग और भी खतरनाक हो जाता है। अंधेरे में गड्ढों का अंदाजा लगाना मुश्किल और निकलना उससे भी ज्यादा जोखिम भरा।स्थानीय लोगों की पीड़ा साफ झलकती है। वे कहते हैं- 'यह गांव की सड़क नहीं कि नजरअंदाज कर दो, यह करछना की मुख्य सड़क है, जो जिले की सबसे व्यस्त राहों में से एक है। अब अगर भी इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई, तो हम शांत नहीं बैठेंगे।' प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि जल्द मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने पर लोग आंदोलन करेंगे। यह कहानी नहीं, बल्कि उस मुख्य मार्ग की दुखभरी सच्चाई है, जिस पर हर दिन हजारों कदम चलते हैं और हर कदम मौत के साए से होकर गुजरता है। सवाल वही है–कब जागेगा प्रयागराज प्रशासन और कब उठेगा इस सड़क को बचाने का कदम?

श्री राम विलास कमला देवी विद्यालय में मनाया गया अद्भुत वार्षिकोत्सव

● मानवीय संवेदनाएं हो रही यांत्रिक : डॉ गंगा प्रसाद शर्मा पूर्व आई ए एस प्रशिक्षक

वक्ताओं ने दिया एकता और अनुशासन का पावन पैगाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। सीतापुर के सकरन क्षेत्र के ग्राम कोलुहापुरवा के श्री रामविलास कमला देवी सेवा समिति द्वारा आयोजित वार्षिकोत्सव एवं छात्र अलंकरण समारोह अत्यंत गरिमामय, प्रेरणादायी एवं वैचारिक वातावरण में सम्पन्न हुआ। यह आयोजन न केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान का साक्षी बना, बल्कि समाज में शिक्षा, संवेदना और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का सशक्त संदेश भी दे गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आई ए एस प्रशिक्षक डॉ. गंगा प्रसाद शर्मा 'गुणशेखर' ने अपने उद्बोधन में गहन सामाजिक यथार्थ को रेखांकित करते हुए कहा कि आज के यांत्रिक होते समाज में मानवीय संवेदनाएँ क्षीण होती जा रही हैं और मशीनवत होती जा रही है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि इंसानियत, मानवता और सहयोग की भावना विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण का अनिवार्य आधार होनी चाहिए। डॉ. शर्मा के अनुसार, शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा समाज की जड़ समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है।इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि जनकवि डॉ. देवेंद्र कश्यप 'निडर',, ने गूढ़ दार्शनिक भाव में कहा– 'ज्ञान प्रगति का पासवर्ड है, जिसके बिना समस्याओं के समाधान का द्वार नहीं खुलता।' उनके विचारों ने उपस्थित विद्यार्थियों व अभिभावकों को आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया। उन्होंने काव्यपाठ के दौरान यह भी कहा कि अनुशासन की डगर न छोड़ो तो मंजिल मिल जायेगी। द्वितीय सत्र के मंच संचालक कवि श्री रोहित विश्वकर्मा ने हास्य और सकारात्मकता से परिपूर्ण काव्य प्रस्तुति देकर वातावरण को ऊर्जावान बनाया, जबकि श्रीमती पिंकी प्रजापति, कवयित्री ने संघर्ष और निरंतरता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से नारी चेतना एवं आत्मबल का संदेश दिया– 'मैं हूँ नदी का किनारा, जो कभी रुकती नहीं।' उनकी कविता ने श्रोताओं के मन में अदम्य साहस का संचार किया। कार्यक्रम का प्रारम्भिक संचालन डॉ. चन्द्रशेखर प्रजापति, उप-संपादक, भाखा अंतरराष्ट्रीय अवधी पत्रिका के द्वारा किया गया। उनके कुशल संचालन ने कार्यक्रम की भूमिका तैयार की। कवि विकास मौर्य 'वीकू' एवं कवि राकेश मौर्य ने क्रमशः आधुनिक भावबोध और लोकभाषा अवधी में उत्कृष्ट काव्य पाठ प्रस्तुत कर श्रोताओं की भरपूर प्रशंसा अर्जित की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रतिष्ठित शिक्षाविद् गुरुजी आर. डी. वर्मा ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए समाज को दिशा देने वाले विचार प्रस्तुत किए। सामाजिक कार्यकर्ता नीतू वर्मा ने बेटियों की शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को सामाजिक विकास का मूलमंत्र बताते हुए विचार रखे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रबन्धक श्री सुशील कुमार मौर्य, प्रधानाचार्य श्री तेजनरायन पाण्डेय, कार्यक्रम संयोजक सुरेंद्रकान्त मौर्य (प्रबन्धक - एल.पी.एल. डी. मेमोरियल एकेडमी) तथा व्यवस्थापक दिलीप कुमार की भूमिका सराहनीय रही। अंत में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, वक्ताओं, कवियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

संक्षिप्त खबरें

सड़क हादसे में वरिष्ठ पत्रकार घायल, पैर में फ्रैक्चर

लालगंज (रायबरेली)। सोमवार को अपने घर से बहन के यहां जा रहे वरिष्ठ पत्रकार अमरेश पटेल उर्फ मिलन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना सराय बैरिया खेड़ा-चक चोरइहा मार्ग पर कनकापुर गांव के पहले हुई।जानकारी के अनुसार, लालगंज थाना क्षेत्र के मीठापुर गांव निवासी पत्रकार अमरेश पटेल सोमवार दोपहर बाइक से अपनी बहन के घर कुर्मी सरांय गांव जा रहे थे। जैसे ही वह गेगासो-लालगंज मार्ग से सराय बैरिया खेड़ा गांव की ओर मुड़े, तभी कनकापुर गांव के पहले एक चार पहिया वाहन के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना उन्होंने गेगासो चौकी इंचार्ज अरविंद चौधरी को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने पैर में फ्रैक्चर होने की पुष्टि करते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि बाद में परिजन उन्हें बेहतर इलाज के लिए फतेहपुर ले गए।पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ओवरटेक करते, बाइकें सामने-सामने टकराईं, दोनों बाइक सवार घायल

हमीरपुर- जनपद के बिवांर थाना खेल मैदान के सामने एसएच 42 पर सोमवार शाम लगभग साढ़े चार बजे दो बाइकें सामने-सामने टकरा गई ,दोनों बाइक सवार घायल हो गए। दोनों बाइक सवार हैलमेट

लगाए हुए थे, जिस वजह से दोनों के चेहरे पर हल्की चोटें आई। निवादा निवासी राजेन्द्र तिवारी अपने जलालपुर स्थित स्कूल से घर वापस लौट रहे थे और निवादा के ही सोमनाथ प्रजापति (राजमिस्त्री) अपने गांव से बिवांर की तरफ आ रहे थे।बिवांर थाना से कुछ पहले, खेल मैदान के सामने रोड पर लगी ट्रकों की कतार को ओवरटेक करते वख्त सोमनाथ की बाइक अपनी सेड से आ रहे राजेन्द्र की बाइक से सामने-सामने टकरा गई।दोनों ही बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। थाना पास ही होने की वजह से पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस से छानी सामुदायिक केंद्र भेज दिया।कस्बा इंचार्ज अंकित बैसला ने बताया, दोनों को बहुत गम्भीर चोटें नहीं हैं, जल्द ठीक हो जाएंगे।

सवा पाँच किलो अवैध गाँजा के साथ आरोपी गिरफ्तार

हमीरपुर- मुस्करा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक युवक को बड़ी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। कस्बा थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश तिवारी ने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल जा रहे अभियान के तहत जानकारी मिली कि कस्बा थाना क्षेत्र के बसवारी गांव का युवक प्रियांशु 25 वर्ष उर्फ गोलू महाराज पुत्र मोहन प्रकाश पचौरी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करता है। जिस पर पुलिस टीम के उपनिरीक्षक राजीव कुमार साहू, उपनिरीक्षक दिनेश प्रसाद, हेड कांस्टेबल कमलेश यादव, कांस्टेबल आकाश कुमार, एवं का0 नरेंद्र सिंह ने मिलकर कार्रवाई की, और गोलू महाराज को बसवारी मौदहा मार्ग में जाकर घेर लिया। और उसकी तलाशी ली गई। तब उसके पास से 5 किलो 280 ग्राम अवैध सूखा गांजा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। जिस पर उसे टीम द्वारा गिरफ्तार कर थाना मुस्करा लाया गया। जहां अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई। बताया कि उक्त अभियुक्त गोलू महाराज का पूर्व में भी आर्म एक्ट जैसी कई धाराओं में जनपद के अलग- अलग थानों में मुकदमा पंजीकृत हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार के गेट पर भारी वाहनों का अतिक्रमण, मरीजों को भारी परेशानी

● अस्पताल गेट पर भारी वाहनों का कब्जा, मरीजों की जान से खिलवाड़

रेलकोच कारखाना के भारी माल वाहनों का अस्पताल गेट के सामने कब्जा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज, रायबरेली। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 232 सड़क किनारे भारी वाहनों की लम्बी कतार लगी रहती है।रेलकोच फैक्ट्री के निकट स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐहार के मुख्य गेट पर रोजाना कारखाने में माल लाने वाले भारी वाहनों का कब्जा बना रहता है। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कई बार आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह प्रभावित हो जाती हैं।भारी वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण चार पहिया वाहन और एंबुलेंस तक अस्पताल परिसर में प्रवेश नहीं कर पातीं। कई बार गंभीर मरीजों को गेट के बाहर ही उतारना पड़ता है, जिससे उनकी जान पर सीधा खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस लापरवाही के चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय लोगों का कहना

स्थानीय निवासी विनय कुमार, पुनीत सैनी, विरेंद्र वर्मा,रामकिशोर, अजय वर्मा,बबलू यादव, शोभित, श्यामू मिस्त्री और राजेश कुमार चौरसिया सहित अन्य लोगों का कहना है कि 'सुबह से शाम तक भारी वाहन अस्पताल के गेट के सामने खड़े रहते हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।' लोगों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो किसी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है।

प्रशासन का पक्ष

इस संबंध में जब डाक्टर निधि वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि 'अस्पताल के सामने खड़े होने वाले भारी वाहनों को हटाने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में अस्पताल की आपात सेवाओं में बाधा नहीं आने दी जाएगी।

पुण्यतिथि पर याद किए गए भाई परमानन्द

हमीरपुर- सुमेरपुर में वर्णिता संस्था के तत्वावधान में विमर्श विविधा के अन्तर्गत क्रांतिकारी भाई परमानंद की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धासुमन अर्पित किये गए।संस्था के अध्यक्ष डा. भवानीदीन ने महान क्रांतिकारी भाई परमानन्द की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि भाई परमानन्द बलि पथ के अडिग राही थे, इनके देश के प्रति योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1876 को झेलम पंजाब में ताराचंद और मथुरा देवी के घर हुआ था। ये योद्धा, लेखक और समाजनिष्ठ थे। देश के क्रांतिकारी आन्दोलन को इन्होंने आधार प्रदान किया। शहीद भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल जैसे युवा क्रांतिकारी के यह प्रेरणा स्त्रोत थे। इनकी भारत का इतिहास, वीर बन्दा वैरागी और मेरी आप बीती जैसी कृतियां प्रसिद्ध है। देश की आजादी के समय भारत विभाजन से दुखी होकर ये कमजोर हो गये और इसी चिंता में 8 दिसम्बर 1947 को इनका निधन हो गया था। इस कार्यक्रम में सिद्धा, प्रेम, सागर, महावीर प्रजापति इलेक्ट्रीशियन, दयाराम सोनकर, रिचा, भोलू सिंह, विकास, रामनरायन सोनकर, सतेन्द्र, राहुल प्रजापति आदि शामिल रहे।

सच्चिदानन्द पैलेस में श्रीमद्भागवत कथा में गूंजा महारास का दिव्य प्रसंग, भाव-विभोर हुए श्रद्धालु

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के ऐहार गांव स्थित प्रसिद्ध बाल्हेश्वर मंदिर के निकट सच्चिदानन्द गेस्ट हाउस में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठवें दिन सोमवार को भगवान श्रीकृष्ण की महा रासलीला का दिव्य प्रसंग सुनाया गया। कथा सुनते ही पूरा परिसर भक्तिभाव से सराबोर हो उठा।कथा व्यास पं. झिलमिल महाराज ने बताया कि जीव का ब्रह्म से मिलन ही महारास कहलाता है। उन्होंने कहा कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में अपनी मधुर वंशी बजाई तो गोपिकाएं सब कुछ त्यागकर उनकी ओर दौड़ी चली आई, क्योंकि श्रीकृष्ण ही गोपेश्वर अर्थात परमात्मा हैं। आत्मा और परमात्मा का यही दिव्य मिलन महारास के रूप में प्रकट होता है।कथा व्यास ने यह भी बताया कि महारास के दौरान भगवान शिव भी माता पार्वती के साथ गोपी वेश में दर्शन के लिए पहुंचे थे। श्रीकृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और मुस्कुरा उठे।

इस प्रकार हरि और हर का पावन मिलन हुआ। इस प्रसंग को सुनकर श्रद्धालुओं की आंखें श्रद्धा से नम हो गई।इसके बाद कथा व्यास ने रुक्मिणी विवाह का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि रुक्मिणी श्रद्धा का प्रतीक हैं, जबकि श्रीकृष्ण विश्वास के प्रतीक हैं। श्रद्धा और विश्वास का संगम ही जीवन को पूर्ण बनाता है। कथा के दौरान श्रीकृष्ण की माखन लीला, दामोदर लीला, मधुराष्टक, बकासुर वध, सटकासुर उद्धार सहित अन्य लीलाओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया। प्रत्येक प्रसंग पर श्रोता जय-जयकार करते रहे। कार्यक्रम में घनश्याम सोनी, किरण सोनी, महेश सोनी, रज्जन गुप्ता, शिवगोपाल गुप्ता,श्री राम मास्टर, अनुज अवस्थी, अतुल मिश्रा, अनुराग, शिवबरन वर्मा, संजू तिवारी, विनोद सोनी, हरिओम सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

खेत में खूनी संग्राम! जमीनी विवाद में दो परिवारों के बीच भीषण संघर्ष, 10 लोग लहूलुहान, दो की हालत गंभीर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के पूरे सनई मजरे कुंडवल गांव में सोमवार दोपहर जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते दो पक्षों के बीच लाठियों और डंडों से खूनी संघर्ष शुरू हो गया। इस भीषण मारपीट में दोनों पक्षों से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है।जानकारी के अनुसार गांव के राहुल और मोतीलाल के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। सोमवार करीब दो बजे मोतीलाल का परिवार विवादित खेत में गेहूं की बुवाई कर रहा था। तभी राहुल का परिवार वहां पहुंच गया और काम का विरोध करने लगा। पहले कहासुनी हुई, फिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग आपस में एक-दूसरे पर टूट पड़े।

इस मारपीट में मोतीलाल पक्ष से जनक दुलारी, मोतीलाल, सुनीता, खुशबू और पूजा घायल हुए हैं। वहीं राहुल पक्ष से राहुल, उनकी मां गणेशा, विनीता, उमा, अर्चना और रोशनी को भी गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को आनन-फानन में सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से जनक दुलारी और मोतीलाल को हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में लिया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के घायलों का इलाज कराया जा रहा है और लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

चार दिन से ठप है पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट, लोग परेशान; दर्ज नहीं करा पा रहे शिकायतें

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के लिए विकास कार्य करने वाली सबसे प्रमुख एजेंसी लोक निर्माण विभाग की पिछले चार दिन से वेबसाइट ठप है। मगर विभाग के अधिकारी बेखबर हैं। जनता परेशान हो रही है, लोग सड़कों और स्ट्रीट लाइटों से संबंधित शिकायतें वेबसाइट पर नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने शिकायतें की हैं वे अपना स्टेटस नहीं जान पा रहे हैं। वहीं परियोजनाओं की प्रतिदिन की निगरानी के लिए बनाया गया विभाग का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम ठप है। विभाग के तमाम आर्डर वेबसाइट पर लोड होते हैं, वह कार्य भी ठप है। वेबसाइट क्यों ठप हुई और कब तक ठीक होगी इस पर अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं हैं, अधिकारी इसे लेकर गंभीर भी नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली लोक निर्माण विभाग में 3000 से अधिक स्टाफ काम कर रहा है। इसमें से 600 से अधिक अभियंता कार्यरत हैं। इस विभाग के पास में 1440 किलोमीटर लंबाई वाली सड़के हैं। विभिन्न सरकारी विभागों की इमारतों का निर्माण और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी इसी विभाग के पास है।

डीएम की अध्यक्षता में आयुष्मान कार्ड के विशेष अभियान की समीक्षा बैठक संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली, जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जनपद में चलाये जा रहे आयुष्मान कार्ड के विशेष अभियान (25 नवम्बर से 25 दिसम्बर 2025) की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न की गयी। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.नवीन चंद्रा एवं नोडल अधिकारी-आयुष्मान भारत डॉ.अशोक कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद रायबरेली के निर्धारित आयुष्मान कार्ड लक्ष्य 1521204 के सापेक्ष 942830 आयुष्मान कार्ड (61.98%) बना लिए गये है।

जिलाधिकारी द्वारा आयुष्मान कार्ड अभियान के सम्बन्ध में समस्त सम्बंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत समस्त शेष बचे लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर संतृप्त किया जाए तथा ऐसे शेष लाभार्थी जिनका नाम कई योजनाओं में डुप्लीकेट, डाटा मिसमैच, मृतक, विस्थापित इत्यादि की लाइन-लिस्टिंग भी इसी अभियान में कर ली जाए। आशा, आँगनवाड़ी, सहायिका एवं BOCW श्रेणी के समस्त शेष बचे लाभार्थियों तथा 70+ श्रेणी के समस्त लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाकर संतृप्त किया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लाको को आगामी समीक्षा बैठक में अपना प्रदर्शन सुधार कर अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अंजुलता, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ, समस्त एस.डी.एम., जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, समस्त अधीक्षक (सामु.स्वा.केंद्र), जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (आई0 सी0 डी0 यस0), जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अधिकारी (नगर पालिका), जिला समाज कल्याण अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त बी.डी.ओ., समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला क्रियान्वयन इकाई आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्यरत (डी0पी0 सी0-डॉ0 सौरभ चौधरी, डी आई एस एम0 अनुराग तिवारी, डी0 जी0 एम0 श्री निवेश श्रीवास्तव, जिला समन्वयक (NRLM), समेत समस्त सी.डी.पी.ओ एवं अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारीयों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी ने किया समाजसेवियों को सम्मानित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली: बीते रविवार को देश की लोकप्रिय सामाजिक संस्था अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी ने देश के अनेक लोगों को 'भारत गौरव रत्न सम्मान' से सम्मानित किया। इस अवसर पर 101 लोगों को सम्मान से नवाजा गया। सम्मान प्राप्त करने में तमाम श्रेणी के लोग शामिल रहें। मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग, कला व साहित्य के क्षेत्र से जुड़े सदस्य व पत्रकारों को भी इस अवसर पर अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में हेम सिंह राणा (कृभको और नेशनल को - आपरेटिव यूनियन के औल इंडिया डायरेक्टर), अरविन्द सक्सेना (पी.ए. टू रेजिडेंट कमिश्नर , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली), जयदीप सिंह (निजी सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्री) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहें।एकंर वरिष्ठ आर्टिस्ट गोपाल सक्सेना के साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी विकास सक्सेना, पी. सी. गुप्ता, शंभू भद्र, सुशील श्रीवास्तव, दीपक चौधरी, मधु वशिष्ठ, बबीता नागर छाबड़ी आदि उपस्थित रहे। यह संस्था पिछले 7 सालों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस मौके पर संस्था की संस्थापिका अध्यक्षा प्रणीता प्रभात ने कहा कि उनका लक्ष्य समाज के उन लोगों को आगे बढ़ाना है जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था के कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है ताकि वे भविष्य में तमाम क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य छोटे बच्चों और युवाओं के साथ काम करना है ताकि इन लोगों को आगे बढ़ने का सही मार्ग मिल सकें।

दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, कारोबारी की मौत से परिवार में मचा कोहराम

हापुड़। हापुड़ में कोतवाली देहात क्षेत्र में पुराने दिल्ली हाईवे पर दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इसमें एक बाइक पर सवार कारोबारी को गंभीर हालत में देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं, दूसरी बाइक पर सवार युवकों के परिजन उनको किसी निजी अस्पताल ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शहर में पुराने दिल्ली हाईवे पर गढ़ मार्ग पर नाले का निर्माण चल रहा है। ऐसे में कुछ दूरी तक दोनों लेन के यातायात को एक साइड से होकर चलाया जा रहा है। रविवार रात करीब आठ बजे मारुति शोरूम के सामने दो बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। इससे दोनों बाइक पर सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक एक बाइक पर सवार दो युवकों को उनके परिजन किसी निजी अस्पताल में लेकर चले गए थे। वहीं शिवनगर के नितिन उर्फ भीम 24 वर्ष वहीं पर घायल अवस्था में पड़ा था। वह लकड़ी का व्यापारी था। पुलिस ने उसको देवनंदनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

अभिभावकों ने परिषदीय विद्यालय देर से खुलने का लगाया आरोप

● अभिभावकों व अध्यापकों के बीच हुई नोकझोंक, विभागीय जिम्मेदार मौन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- मौदहा विकास खण्ड क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों का तय समय से खुलना और शिक्षण में लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चे भुगत रहे हैं।वहीं इसका विरोध करने पर शिक्षकों द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने की शिकायतें कर बच्चों के अभिभावकों को झूठे केस में फंसाने मामले भी आते रहते हैं। लेकिन अध्यापकों पर विभागीय कार्यवाही नहीं होने की वजह से क्षेत्र के शिक्षा के मंदिर लगातार बदनाम हो रहे हैं और राजनीतिक का अखाड़ा बनते जा रहे हैं।ताजा वाकया सोमवार का है।सिलौली गांव के स्कूल में तैनात अध्यापकों पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए सैकड़ो ग्रामीण स्कूल पहुंच गए इस दौरान शिक्षकों और अभिभावकों में तीखी झडप भी हुई।मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिलौली स्थित स्कूल में तैनात शिक्षकों रामलखन सोनी,राजकुमार गुप्ता और हरिमोहन गुप्ता पर सैकड़ो ग्रामीणों ने शिक्षण कार्य में रुचि न लेने, बच्चों को जातिसूचक शब्द बोलने, स्कूल में घूमपान करने और अपनी गाडियां धुलवाने सहित मिडडे मील भोजन घटिया परोसने जैसे गंभीर आरोप लगाते ग्राम प्रधान सहित ग्रामीणों और अध्यापकों में नीखी नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने तीनों अध्यापकों के ट्रांसफर और विभागीय कार्यवाही की मांग की है। जबकि खण्ड शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार कमल ने मामले की जांच के बाद नोटिस जारी करने और विभागीय कार्यवाही करने की बात कही है।

बताते चलें कि, बीते दिनों विकासखण्ड क्षेत्र के सिजनौडा ,पढोरी और भैंसता गांवों में भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं ,लेकिन विभाग द्वारा मामलों को गम्भीरता से न लेने पर बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर प्रभाव पड़ रहा है।

मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल हुई महिला की इलाज दौरान हुई मौत, परिजनों में छाया मातम

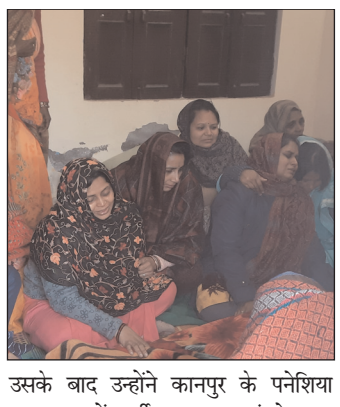

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुरः- कस्बा/थाना बिवांर निवासिनी मानकुंवर (67)पत्नी डॉ राजाभइया कुशवाहा को बीते 2 दिसम्बर की सुबह सड़क किनारे कूड़ा फेंककर लौटते वख्त तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। द्वबाइक की जोरदार टक्कर और सड़क पर गिरने से सिर पर गंभीर चोट आ गई थी।परिजनों पहले जिला अस्पताल ले गए लेकिन सिर और गंभीर चोट आने से खून का बहना बंद नहीं हो रहा था जिस वजह उन्हें जिला अस्पताल से कानपुर रिफर कर दिया गया। परिजन पहले तो कानपुर के न्यूरॉन अस्पताल ले गए लेकिन हालत ज्यादा खराब होने के वजह से भर्ती करने से इनकार कर दिया।मृतका के पुत्र डॉ जीतू ने बताया कि उसके बाद उन्होंने कानपुर के पनेशिया अस्पताल में भर्ती कराया ,जहां ब्रेन का ऑपरेशन हुआ।बताया ऑपरेशन के बाद फिर हुआ खून का रिसाव शुरू हो गया ,जिसके बाद इलाज के लिए ग्वालियर ले गए ,लेकिन ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में इलाज दौरान रविवार सुबह लगभग साढ़े आठ बजे मौत हो गई।पोस्टमार्टम कराकर लौटे परिजनों ने सोमवार सुबह नम आँखों से अंत्येष्ठि की।

वहीं मृतका के पुत्र डॉक्टर जीतू ने पुलिस पर भी हीलाहवाली का आरोप भी लगाया है ,बताया कि तहरीर देने पर प्राथमिकी तो दर्ज कर ली थी लेकिन कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की। थाना प्रभारी नन्दराम ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

भटकी हुई मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को पुलिस ने घर पहुँचाया

भदोही। मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए भदोही पुलिस ने एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को सुरक्षित उसके परिजनों तक पहुँचाकर सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। घटना 06 दिसंबर की रात करीब 10 बजे की है, जब पीआरवी 7673 को सूचना मिली कि थाना औराई क्षेत्र के भगवानपुर गांव में एक आंशिक रूप से विचलित महिला भटक कर पहुंच गई है। सूचना मिलते ही पीआरवी टीम तत्काल मौके पर पहुँची और महिला को सुरक्षित मिशन शक्ति केंद्र, औराई ले जाया गया। वहां तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने धैर्यपूर्वक व सहजता से बातचीत कर उसके परिजनों का पता लगाया। महिला के परिजन ग्राम सागरपुर बवई, थाना सुरियावां निवासी हैं। वे तत्काल औराई आने में असमर्थ थे, ऐसे में पुलिस टीम ने स्वयं महिला को उसके घर पहुंचाकर परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर दिया। महिला को सुरक्षित घर पहुंचाने की यह संवेदनशील पहल परिजन ही नहीं, बल्कि आमजनमानस द्वारा भी खूब सराही जा रही है। पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिमन्यु मांगलिक ने भी पुलिस टीम की तत्परता और मानवीय कार्य की सराहना की।

धनुष यज्ञ की लीला का किया जीवंत मंचन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- मौदहा विकासखण्ड क्षेत्र के गांव इचौली स्थित मढ़ली माई मन्दिर प्रांगण में चल रहे 31 शतचंडी महायज्ञ में अंतिम दिन रामलीला महोत्सव में सोमवार को धनुष यज्ञ और लक्ष्मण-परशुराम संवाद का जीवंत मंचन किया गया। रात भर चले मंचन में परशुराम-लक्ष्मण के ऊंचे स्वर गाँव में गूंजते रहे। रामलीला मंडली चित्रकूट के कलाकारों ने रामलीला मंचन की शुरुआत से पूर्व भारत माता गीत गाकर झांकी पेश की। उसे देखकर दर्शक मोहित हो गये। कार्यक्रम में माता सीता के स्वयंवर की तैयारी शुरू हो गयी। राजा जनक ने दूर दूर के राजाओं को आमंत्रण दिया। राजा महाराजाओं ने भागीदारी कर सीता माता के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन माता से विवाह करने के लिए कोई भी राजा, महाराजा धनुष तोड़ना तो दूर उसे हिला भी नहीं सका। गुरु की आज्ञा लेने के बाद भगवान श्रीराम ने जैसे ही धनुष तोड़ा वैसे ही रामलीला प्रांगण में बैठे दर्शकों ने तालियां बजायी और जय श्री राम के नारे लगाये। शहनाई वादन होने लगी तथा स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं और राम सीता का विवाह हुआ। धनुष टूटते ही परशुराम जी आये और क्रोधित होते हुये धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूंछा। तो नाराज लक्ष्मण का उनसे संवाद हो गया। लक्ष्मण परशुराम संवाद देरशाम तक चला द्य इस मंचन को देखने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे।

डिजिटल हिंसा के प्रति छात्राओं व महिलाओं को किया गया जागरूक

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हमीरपुर- कुरारा विकासखण्ड क्षेत्र के चंदूपुर गांव मे 16 दिवशीय अभियान के अंतर्गत डिजिटल हिंसा से बचाव हेतु युवतियों से चर्चा करते हुए डिजिटल हिंसा की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। चंदूपुर गांव मे 16 दिवसीय अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे डिजिटल हिंसा जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। यह आयोजन पंचायत घर चंदूपुर में किया गया। समर्थ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी बृजेश कुमार श्रीवास्तव, आंगनबाडी कार्यकत्री प्रीति निषाद, समूह से रुक्मणि और खुशहाली अड्डा की ममता में महिलाओं ओर किशोरियों को जागरूक किया। इस दौरान महिलाओं, युवतियां और युवतियों से चर्चा करते हुए डिजिटल हिंसा की रोकथाम हेतु जागरूक किया गया। उन्होने बताया कि पासवर्ड मजबुत रखें। अंजान लिंक को न खोले। हर किसी से साथ ओ टी पी शेयर नहीं करे। और न ही पासवर्ड बताए। अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल को हमेशा सुरक्षित रखें। पर्सनल सिंगल फोटो प्रोफाइल शेयर नहीं करे। हर किसी के साथ अपनी लोकेशन शेयर नहीं करे। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति निषाद द्वारा पोषाहार का वितरण किया। सभी लाभान्वित समुदाय गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, सहित बच्चों को पोषाहार प्रदान किया।